



88-
16/8/82
AUG 1982

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 1982/फाल्गुन 5, 1903

No. 34]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 1982/PHALGUNA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

परिशिष्ट 1

सार्वजनिक सूचना संख्या 10 आई०टी०सी० (पी०एम०)/82

वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 10 आई०टी०सी० (पी०एम०)/82, दिनांक 24 फरवरी, 1982 का परिशिष्ट

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1982

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय :—विदेशी आर्थिक सहयोग निधि ऋण करार सं० आई०डी०पी०-11 और आई०डी०पी०-12 (दूर संचार परियोजना सं० 3 और 4 के अधीन माल और सेवाओं के आयात के लिए लाइसेंस शर्तें)।

जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ०ई०सी०एफ०) द्वारा प्रदान किए गए दूर संचार परियोजना (3) के लिये येन 5.0 बिलियन के येन क्रेडिट के अधीन माल और सेवाओं के आयात के सम्बन्ध में लाइसेंस शर्तें।

खण्ड 1. सामान्य शर्तें

निसिख संख्या-आई०पी०सी० 23 (26)/82—डाक एवं तार महानिदेशालय की दूर संचार परियोजना सं० 3 और 4 की आयात आवश्यकताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आई०सी०एफ० ऋण करार सं० आई०डी०पी०-11 और आई०डी०पी०-12 का येन 5.0 बिलियन और येन 9.4 बिलियन के येन क्रेडिट के अधीन माल और सेवाओं के सम्बन्ध में आयात लाइसेंस जारी करने से सम्बन्धित जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट 1 और 2 में दी गई हैं, उन्हें जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है।

1(1) डाक एवं तार महानिदेशालय की दूर संचार परियोजना की आयात आवश्यकताओं को वित्तदान करने के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ०ई०सी०एफ०) द्वारा प्रदान किया 5.0 बिलियन येन का ऋण विकासशील देशों के लिए खुला है। तबनुसार, इस क्रेडिट के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान और अनुबन्ध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती हैं। ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पात्र होत देश होंगे।

गणि नारायणस्वामी, मुख्य नियन्त्रक आयात नियंत्रित

1(2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मदों और उसी मूल्य के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महानिदेशालय, तकनीकी

विकास/पूँजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो। इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस (सी०) का मूल्य येन 5,600 मिलियन (लागत बीमा-भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए।

आयात लाइसेंस का रूप में मूल्य, राजस्व विभाग (सीमा शुल्क) द्वारा अधिसूचित विनियम दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रचलित दर और मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० 78 आई०टी०सी० (पी०एन०)/74 दिनांक 8 जून, 1974 के पैरा-2 के अनुसार आयात लाइसेंस में संकेतित दर पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख है कि सीमा शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस (सी) में विनिर्दिष्ट मुद्रा विनियम दर पर लाइसेंस मूल्य के नाम डालेंगे। लाइसेंस पर एक शीर्षक "जापानी येन ऋण सं० आई०पी०डी०-11" प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में "एस/जेसी" कोट होगा। डी०जी०पी० एण्ड टी० की आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र में भी इसे दुहराया जाएगा, जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

1(3) लागत बीमा भाड़ा के आधार पर केवल डी०जी०पी० एण्ड टी० के नाम में लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

1(4) डी०जी०पी० एण्ड टी० की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस इस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं। लेकिन, कुल मूल्य येन 5,600 मिलियन (लागत बीमा भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा (1) में कहा गया है।

1(5) आयात लाइसेंस की वैधता में वृद्धि डी०जी०पी० एण्ड टी० द्वारा आवेदन करने पर 31-12-1985 तक दी जा सकती है। इससे आगे की वृद्धि यदि कोई हो तो उसके लिए आवेदन आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजा जाना चाहिए।

1(6) क्रेडिट के अधीन वित्त बान किए जाने वाले आयात, आयात लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत् स्थापित संलग्न माल और सेवाओं की सूची तक प्रतिबंधित है।

1(7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अधिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अधिकर्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे।

1(8) पक्के अनुदेश अनुबंध 1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी संभरकों को जहाज पर्यन्त निःशुल्क के आधार पर लिए जाने चाहिए और ये आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीने की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। भाड़ा और बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रूप में भारत में देय होगा। "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंस धारी द्वारा दिए गए उन त्रय आवेशों से है जो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित त्रय संविदा हो। विदेशी संभरकों के भारतीय अधिकर्ताओं के आदेश या ऐसे भारतीय अधिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आवेश स्वीकार्य नहीं है।

1(9) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण वस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीने के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग डब्ल्यू०ई०-1 अनुभाग को

नहीं पहुंच आते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(8) में यथा उल्लिखित पक्के आवेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आवेश क्यों नहीं दिए जा सकते इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आवेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), मार्च ब्याक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसे वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय प्राधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों में बैंक गारंटी साथ पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र तुरन्त रूप से अमा कराने आदि की स्वीकृति सुविधाओं की अनुमति देंगे।

1(10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिए। माल के पोतलदान पर अलग-अलग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेके में नकद आधार पर अर्थात् पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किस्म की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए:—

"साख पत्र की प्राप्ति के बाद महीने परन्तु अधिक से अधिक के अन्त तक पूर्ण किया जाना है। पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-12-1985 के बाद की न हो।"

खण्ड 2. संभरण ठेके का समाप्ती करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें

2(1) ठेके का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य येन में (येन की जिस के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अधिकर्ता का कमीशन यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रूप में चुकाना चाहिए।

भारतीय रूप या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। त्रय आवेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आवेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2(2) प्रो०ई०सी०एफ० येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) के अधीन माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए विस्तृत निवेश अनुबंध-2 में दिए गए हैं। लेकिन, यदि माल और सेवाओं के लिए औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से भिन्न अधिप्राप्ति क्रियाविधि अपनाते या विचार है जिसका भुगतान ऋण की प्राप्ति से से किया जाएगा तो इसका पूर्व अनुमोदन निधि से प्राप्त किया जाएगा और अधिप्राप्ति क्रियाविधि(यों) अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और कारणों सहित निधि को भेजे जाएं।

माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए बोलियां आमंत्रित करने से पहले बोलिकारों के लिए सभी नोटिस, आवेशों, बोलों प्रपत्र, प्रस्तावित संविदा, विनिर्दिष्टकरण और ड्राईस और बोलों लगाने से सम्बन्धित अन्य सभी दस्तावेजों की प्रतियां पूर्व अनुमोदन के लिए निधि को भेजी जाएंगी। प्रो०ई०सी०एफ० का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त दस्तावेज/

प्राप्ति के पत्र दो प्रतियों में आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजे जाएंगे।

2(3) विदेशी संभरक का भुगतान, उनके नाम में भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा 1979-80 के लिए ओ.ई.सी.एफ. येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं. ओ.ई.सी.एफ. 11 के अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साख-पत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसका खोला नीचे खण्ड-6 में दिया गया है।

2(4) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा की जानी चाहिए। लेकिन, कुछ विशेष मामलों में, एक से अधिक संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने का लिये के दुरुस्त बाव वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

2(5) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे या पात्र स्रोत देशों में आर्थिक किए गए तथा पंजीकृत किए गए पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा शासित वैध व्यक्ति होंगे।

2(6) संविदा में घोषण

प्रत्येक संविदा में संभरकों द्वारा पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :—

—मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि संभरित किया जाने वाला माल ————— में (पात्र स्रोत देश) उत्पादित है।

मैं, अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र स्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सत्र के अनुसार 30 प्रतिशत से कम है :—

आयातित लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य + आयातक शुल्क
————— × 100

संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य
और

मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि ————— (पात्र स्रोत देश का नाम) में ————— (कम्पनी का नाम) समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र स्रोत देश के राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है।

2(7) अपात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयात

जिन वस्तुओं में अपात्र स्रोत देशों में बंसी हुई सामग्री निहित है उसका वित्तियन किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार मक्का आधार पर आयातित भाग 30 प्रतिशत से कम हो :—

आयातित लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य + आयातक शुल्क
————— × 100

संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य

खण्ड 3. संभरण ठेकों से समाविष्ट की जाने वाली शर्तें

3(1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए :—

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ.ई.सी.एफ.) के बीच दूर संचार परियोजना (3) के लिए येन क्रेडिट सं. ओ.ई.सी.एफ. 11 (परियोजना सहायता) से सम्बन्धित 15 अक्टूबर 1981 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा।

(ख) संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ.ई.सी.एफ.) के बीच येन क्रेडिट

संख्या ओ.ई.सी.एफ. 11 से सम्बन्धित 15 अक्टूबर 1981 को हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत बैंक ऑफ इण्डिया टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साख-पत्र के माध्यम से किए जाएंगे।

(ग) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और वास्तविकताओं को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओ.ई.सी.एफ. द्वारा येन ऋण के अधीन अंगेजित हो।

(घ) 2(6) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र तीन प्रतियों में।

3(2) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हों तो संभरण संविदा के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय दूतावास टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास टोकियो को, पोतलदान शामिल माल की सुपूर्दगी के कार्यक्रम से अवगत कराएगा और कम से कम 6 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक इच्छुक हों, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक का प्रत्येक पोतलदान के पश्चात् आवश्यक स्थिति देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खण्ड 4. विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ.ई.सी.एफ.) द्वारा ठेके का अनुमोदन

4(1) लाइसेंसधारी को पक्के आवेदन देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर ओ.जी.पी.एण्डटी. और विदेशी संभरकों दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां जो विदेशी संभरकों द्वारा लिखित में पुष्टि आवेदन के साथ हो या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां संगत वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

4(2) उपर्युक्त क्रियाविधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विषय वस्तु के लिए अनिवार्य आशोधनों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी।

4(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग, दूर संचार परियोजना (3) के लिए येन क्रेडिट सं. ओ.ई.सी.एफ. 11 (परियोजना सहायता) के अन्तर्गत वित्तियन करने के लिए विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ.ई.सी.एफ.) को संविदा वस्तुओं की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा।

खण्ड 5. विदेशी संभरकों को भुगतान साख-पत्र क्रियाविधि

5(1) विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ.ई.सी.एफ.) से ठेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग जापान अनुभाग द्वारा ओ.जी.पी.एण्डटी. और सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक को उसकी सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद ओ.जी.पी.एण्डटी. को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद सी.ए.ए.एण्डटी. कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू.सी.ओ. बैंक ब्रिडिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबन्ध-3 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करना चाहिए। सी.ए.ए.एण्डटी. संश्लित विदेशी संभरक के लिए संलग्न प्रपत्र-4 में एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा। जो सम्बद्ध विदेशी संभरक के नाम में (वास्तविक आयातों के लिए संलग्न अनुबन्ध-5) के रूप में या (सेवाओं के लिए) अनुबन्ध 6 के रूप में अपरिवर्तनीय साख पत्र खोलने के लिए भारतीय बैंक को टोकियो शाखा को भेजा जाना चाहिए। प्राधिकार पत्र की प्रतियां (विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि ओ.ई.सी.एफ.) भारतीय दूतावास टोकियो भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएंगी।

5(2) प्राधिकार पत्र मिलने पर, भारतीय बैंक, टोकियो अनुबन्ध-5 (मास्तविक प्रायातों के लिए लागू होता है) या 6 (सेवाओं के लिए लागू होता है) के अनुसार सम्बन्धित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (सी०ई०सी०एफ०) भारतीय वृत्तावास टोकियो भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा।

सी०ए०ए० एण्ड ए० से प्राधिकार पत्र के आधार पर साखपत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि संविदा संशोधन या अन्यथा के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे सभी प्राधिकारपत्र/साख पत्रों के संशोधनों पर स्वतः लागू होगी।

5(3) माल का पोतलदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकों के माध्यम से साखपत्र में उल्लिखित वस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इण्डिया टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि वस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इण्डिया टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद प्रायातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक निधि से प्राप्त करेगा।

5(4) साखपत्र को खोलने रख-रखाव और परिवालन पर किए गए सभी खर्च विदेशी संभरकों के लेखों में आएंगे। धनः भारतीय बैंक टोकियो संभरक बैंक से सभी खर्च प्राप्त करेगा दस्तावेजों की संभाल के रखने और मोल-मोल करने और अन्य आकस्मिक खर्च भी संभरकों द्वारा किए जाएंगे।

संभरकों को भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा जहाज पर्यन्त निःशुल्क माल की लागत के भुगतान की तिथि और भी०ई०सी०एफ० द्वारा प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच के समय का व्याज भारतीय बैंक उनके और भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के साथ 25-3-80 को हुए समझौते की शर्तों के अनुसार प्राप्त करेगा और इसके प्रतिपूर्ति भारतीय वृत्तावास टोकियो द्वारा की जाएगी। भारतीय वृत्तावास जापान द्वारा व्याज भुगतान पर किया गया खर्च डाक एवं तार विभाग [दिखें खण्ड ख-6(4)] से प्राप्त किया जाएगा।

खण्ड 6. रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व

6(1) भारतीय बैंक, टोकियो संगत प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट में संकेतित अनुसार सी०जी०पी० एण्ड टी० के प्राधिकृत बैंकर को परामर्श जहाजरानी वस्तावेज भेजेगा और बैंकर इसके बबले में यह सुनिश्चय करेगा कि जहाजरानी वस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक तीस हजारी दिल्ली में रुपया निक्षेप कर दिया गया है। विदेशी संभरकों को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए सार्वजनिक सूचना सं०-74 आई०टी०सी०(पी०एन०)/74, दिनांक 31-5-1974 में निर्धारित विधि के अनुसार भारत सरकार के लेखों में जमा किए जाएं। विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनियम की दर भुगतान की तारीख को लागू विनियम की वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं० 109 आई०टी०सी०(पी०एन०)/74, दिनांक 3-8-74 और सं० 8 आई०टी०सी०(पी०एन०)/76 दिनांक 17-1-1976 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह "के डिपॉजिट्स एण्ड एक्वासिज-843 सिविल डिपॉजिट्स फार परवेजिज एटस्ट्रा एंशोअर अन्डर केडिट्स खोन एप्रीमेंट" खोन फ्राम वि गवर्नमेंट आफ जापान 6.0 बिलियन येन केडिट सं० आई०जी०पी०-II फार दूर संचार परियोजना सं० (3) होना चाहिए।

6(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी दिल्ली में सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना सं० 184 आई०टी०सी०(पी०एन०)/68, दिनांक 30-8-68, सं० 233 आई०टी०सी०(पी०एन०)/68, दिनांक 24-10-68 सं० 132 आई०टी०सी०(पी०एन०)/71 दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई०टी०सी०(पी०एन०)/74 दिनांक 31-5-74 और सं० 103 आई०टी०सी०(पी०एन०)/76 दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित तरीके में जमा होना चाहिए।

6(3) भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह प्रतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालों को भरते समय प्रायातकों/उनके बैंकों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 132 आई०टी०सी०(पी०एन०)/71, दिनांक 5-10-1971 के पैरा-2 में निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेपण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ध्येरे" में निरपवाद रूप से निश्चित किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ध्येरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए:-

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र, संख्या और दिनांक

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।

उसके पश्चात् सी०ए०ए० एण्ड ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संबंध देते हुए और बीचक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी०ए०ए० एण्ड ए० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणः भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक, टोकियो की अवायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान वस्तावेजों की प्राप्ति 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी०ए०ए० एण्ड ए० वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

6(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाहसंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्राप्ति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पूर्णांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस०" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई को भेजना चाहिए। भारतीय वृत्तावास, टोकियो द्वारा भारतीय बैंक, टोकियो को व्याज खर्चें प्राप्ति के सम्बन्ध में येन की समतुल्य रुपए में किए गए भुगतान की गणना भी उपर्युक्त खण्ड-6 की कंडिका 6(1) में निर्धारित विधि के अनुसार की जाएगी। मुख्य लेखा अधिकारी, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम में जमा किया जाएगा जिसके लिए सी०ए०ए० एण्ड ए० उचित अनुदेश जारी करते रहेंगे।

खण्ड 7. विविध व्यवस्थाएँ

7(1) आयात लाहसंस के उपयोग करने की रिपोर्टें

आयातक का पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साखपत्र खोलने के बाद तक मासिक रिपोर्टें सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

7(2) संभरकों की विशेष शर्तों के बारे में अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी के आयात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबन्धों से संभरक को अलग करना देना चाहिए जो माल के लाने में संभरक पर प्रभाव डालती हैं।

7(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंस और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों अनुबन्ध 3 में "भुगतान की शर्तों" के अन्तर्गत प्रष्टी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से सम्बद्ध व्यवस्थाएँ शामिल होनी चाहिए।

7(4) अधिपक्ष अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों में संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट समझौते (परियोजना सहायता) सं० आई०पी०डी०पी०-II के अधीन सभी भागधारियों को विदेशी आर्थिक सहयोग निधि, जापान (आई०सी०एफ०) के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों, अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

7(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपयुक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्गत (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

7(6) अनुबन्धों की सूची

1. अनुबन्ध-1 पात्र स्रोत देशों की सूची
2. अनुबन्ध-2 अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्गदर्शन
3. अनुबन्ध-3 अधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध
4. अनुबन्ध-4 प्राधिकार पत्र का प्रपत्र
5. अनुबन्ध-5 साख पत्र का प्रपत्र (वास्तविक आयातों के लिए लागू)।
6. अनुबन्ध-6 साख पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू)

अनुबन्ध 1

पात्र स्रोत देशों की सूची

- (क) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र
(ख) ओ०पी०डी०सी० से भिन्न विकासशील देश

1. अफ्रीका उत्तरी सहारा

मिस्र
मोरोको
सुभीशिया

2. अफ्रीका दक्षिणी सहारा

भंगोला
बोत्सवाना
बरण्डो
कैमेरून
कैप वडी द्वीप समूह
केन्द्रीय अफ्रीका गणसंघ
चाड
कमोरो द्वीप समूह
कांगो डेलीमें का गणसंघ
भूमध्य गिनी (1)
इथोपिया

गाम्बिया
गाना
गिनी
आइवरी कोस्ट केनिया
लेसोथो
लाइबीरिया
मालागासी गणसंघ
मालावी
माली
मारितीनिया मारीशस
मुजाम्बीक
नाइजर
पुर्तगाली गिनी
रियूनियन
रोडे़शिया

रवान्डा
सेंट हेलेना और जेम् (2)
स.ओटोम और प्रिंसिपल
सेनेगाल
सिबलीज
सियरा लियोन
सोमालिया
सूडान
स्वाजी लैण्ड
टेरी आयर्स और इसास (3)
टोंगो
युगाण्डा
तंजानिया संयुक्त गणसंघ
अपर बोटा
जाइरे गणसंघ
जाम्बिया

3. अमेरिका उत्तरी और केंद्रीय

बहामास
बारबाडोस
बेलीज
बेरमुड
कोस्टारिका
क्यूबा
डोमिनिकान गणसंघ
एल साल्वेडोर
ग्वाटेमाला
ग्वाटेमाला
हैती
होण्डुरस
जेमेका
मार्टिनिक्का
मेक्सिको
नीदरलैण्ड एमटिलीज
निकार गुवा
पनामा
सेंट पियरों और मिक्यीलोन
ट्रिनिडाड और टोबोगो
बेस्ट इण्डो (साख) एन०आई०डी०
(क) संबंधित राज्य (4)
(ख) आश्रित (5)

4. दक्षिणी अमेरिका

अर्जेंटीना
बोलीविया

भाजील
चिली
कोलम्बिया
फाल्कलैण्ड द्वीप समूह
फ्रांसीसी गिनी
गुयाना
पारग्वे
पीरू
सुरिनाम
उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया

बेहरीन
इजराइल
जोर्डन
लेबनान
ओमान
सिरिआई अरब गणतंत्र
यूनाइटेड अरब एमीरात (3)
यमन अरब गणतंत्र
यमन जनवादी डी०आर० (4)

- (1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, फरनेन्डोपो द्वीप सहित।
- (2) निम्नलिखित द्वीपों सहित :—
भर्सेशन, ट्रिस्टन डा वन एक्सोसिविल्स, नाइटिंगेल गाक
- (3) मुख्य द्वीप समूह, अरब, बोनेरे क्युराकाओ साहा, सेंट यूस्टासिट
जेन्ट मार्टिन (वक्षिणी भाग)।

6. दक्षिणी एशिया

अफगानिस्तान
बांगला देश
भूटान
बर्मा
भारत
मालदीव
नेपाल
पाकिस्तान
श्री लंका

7. दक्षिण पूर्वी एशिया

ब्रुनी
हुंगकांग
कम्बोडिया गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र
लाओस
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान
थाईलैण्ड
तिमोर
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

8. ओसिनिया

कोक द्वीप समूह
फिजी
गिल्बर्ट और इलाहस द्वीप

फ्रांसीसी पोलिनेशिया (5)
नीरू
न्यू कैलेडोनिया
न्यू हेब्रिडियन टेरिटोरी (फ्रा० और के०)
निय
पेसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
पापूवा न्यू गिनी
सोलोमन द्वीप समूह (फ्रा०)
टोंगा
वालिस और फुतुना
पश्चिमी समाओ

9. यूरोप

साइप्रस
जिब्राल्टर
ग्रीक
माल्टा
स्पेन
टुर्की
यूगोस्लाविया

- (1) मुख्य द्वीप समूह एंडिगुवा, बोमिनिका, ग्रेनाडा, सेंट किट्स
(सेंटकोरिस्टोफे) नेविस-एंथमुला, सेंट लूसिया और सेंट
विसेंट।
- (2) मुख्य द्वीप समूह, मोन्तेसेरात, ओमान, तुर्कस और काईकोस
और ब्रिटिश अरजिन द्वीप समूह।
- (3) अजमान, कुवई, फुजाइरह, रास अल खेमाह, शारजाह और
उम अल क्वैन।
- (4) अरब और विशिष्ट सुलतनत और एमीरात सहित।
- (5) सोसायटी द्वीप समूह (साहित्यी सहित) को शामिल करते हुए
भास्ट्राल द्वीप समूह टुआमोटु जम्बीअर ग्रुप और मार्कोस
द्वीप समूह।
- (6) पेसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश, कोरीलीन द्वीप समूह,
मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)।

(क-2) ओ०बी०ई०सी० के सदस्य या सहयोगी देश

अल्जीरिया
बोस्निया
लिबियन अरब गणतंत्र
गोबान
नाइजीरिया
इक्वेडोर
बेन्जुएला
ईरान
ईराक
कुवैत
कातार
सऊदी अरब
असुधानी
इण्डोनेशिया

अनुबन्ध-2

ओ०ई०सी०एफ० द्वारा व्यवस्थित परियोजना ऋण के अधीन मास और सेवाएं
अधिप्राप्ति करने के लिए मुख्य मार्ग-दर्शन

1. बिजायन

प्राथमिक सुली अन्तर्राष्ट्रीय निवेश के अधीन सभी संविदाएं बोली
प्रामाणित करने के लिए ऋणी देश में सामान्य प्रचार के लिए कम से कम

एक समाचार पत्र में विशिष्ट होना चाहिए। विज्ञापन के लिए बोली प्रामाणिक करने की प्रतियां पात्र स्त्रोत देशों के स्थानीय प्रतिनिधियों को भी तुरन्त प्रेषित की जानी चाहिए।

2. बोली के दस्तावेज और संविदाएं

2.1 बोली बाण्ड या बोली की गारंटियां साधारण आवश्यकताएं हैं लेकिन इनको इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उचित बोली कार हतोत्साह हो जाए। बोली खुलने के पश्चात् जैसे ही संभव हो बोली बाण्ड अथवा गारंटियां असफल बोलीकारों को रिहा कर देना चाहिए।

2.2 संविदा की शर्तें

संविदा के प्रशामन और उसके अधीन किए गए किसी परिवर्तनों में की गई संविदा की शर्तों में प्रायातक और ठेकेदार या संभरक के अधिकार और दायित्व और यदि प्रायातक द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त किया है तो उसके अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। संविदा की परम्परागत सामान्य शर्तें, जिनमें से कुछ का उल्लेख इन निर्देशन बिन्दुओं में किया गया है के अतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और स्थिति के लिए उपर्युक्त विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए।

2.3 संविदाओं की किस्म और प्रकार

संविदाएं निष्पादित काम के लिए ईकाई मूल्य के या प्रावेधित मकों के या एक मुश्त कीमत के या संविदा के विभिन्न भागों के लिए दोनों के सम्मन्ध के आधार पर प्रदान किए जाने वाले माल या सेवाओं के अनुसार की जा सकती हैं और बोली लगाने वाले दस्तावेजों में चुनी गई संविदा की किस्म की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। वास्तविक मूल्य की प्रति पूति पर मुख्यतः आधारित संविदाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निधि को स्वीकार्य नहीं हैं। इंजीनियरिंग उपस्कर और निर्माण के लिए उसी पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल संविदाएं (टर्नकी संविदाएं) यदि ऋणी देश के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभ प्रदान करें तो वे स्वीकार्य हैं।

2.4 पात्र संभरक

वे नियतक या संभरक जिनके माल एवं सेवाओं का बिल्लवान ऋण की रकम में से किया जाना है (जिसे इसके बाद "पात्र संभरक" कहा गया है) पात्र स्त्रोत देशों से राष्ट्रिक होंगे और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे :—

- (1) अधिदान किए गए जेयरों का एक बड़ा भाग पात्र स्त्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा रखा जाएगा।
- (2) पूर्णकालिक निदेशकों का बहुमत पात्र स्त्रोत देशों के राष्ट्रिकों का होगा।
- (3) ऐसे न्यायिक "व्यक्तियों" का पंजीकरण पात्र स्त्रोत देशों में होगा।

3.1 संविदा की कीमत

(क) संविदा कीमत आपान येन में दर्शाई जानी चाहिए यशर्तें कि संविदा कीमत का वह भाग ठेकेदार ऋणी के देश में खर्च करेगा ऋणी की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए।

(ख) मूल्य समंजन संविदाएं

बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि पक्की कीमतों में वृद्धि की आवश्यकता है अथवा बोली की कीमतों में वृद्धि स्वीकार्य है। यदि संविदा के प्रमुख लागत अवयवों अर्थात् श्रम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता है तो संविदा की कीमतों में समंजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

कीमतों के समंजन के लिए विशिष्ट सूच बोली दस्तावेजों में साफ-माफ परिभाषित होना चाहिए। माल की सप्लाय के लिए संविदाओं में कीमतों के समंजन की उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन सिविल कार्यों के लिए संविदाओं में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को प्रायः शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

एक वर्ष के अन्दर सुपुर्दे किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समंजन की व्यवस्था प्रायः नहीं होती चाहिए। ये मार्ग निर्देशन बिन्दु उन विभिन्न उपयोगों के परिचय का आभास नहीं कराती हैं जिनके द्वारा संविदा मूल्य समंजित किया जा सके।

(ग) बोमा

सफल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमे की किस्तों का बोली दस्तावेजों में संक्षेप वर्णन होना चाहिए।

3.2 दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा या विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण प्रादेश से समर्थित ऋण प्रादेश जो भारतीय प्रायातक द्वारा विदेशी संभरक को दिया गया है, या इनकी फोटो प्रतियां भी फण्ड को स्वीकार्य हैं।

3.3 प्रत्येक संविदा में संभरक की पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :—

"मैं (हम एतद्द्वारा यह उल्लेख करते हैं कि मेरी (हमारी) कंपनी पात्र संभरक है क्योंकि शीयरी का प्रतिशत (%) (पात्र स्त्रोत देश) के राष्ट्रिकों द्वारा रखा गया है और प्रतिशत () निदेशक (पात्र स्त्रोत देश) के राष्ट्रिक है और मेरी (हमारी) कंपनी (पात्र स्त्रोत देश) में पंजीकृत कराई गई है।

4.1 मापवण्ड

यदि उन राष्ट्रीय मापवण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए कि आपान औद्योगिक मापवण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर-राष्ट्रीय मापवण्ड को पूरा करने वाली पण्यवस्तुएं जो मापवण्डों की कोटि के बराबर या इससे अधिक मापवण्ड का सुनिश्चय करती हैं, उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा।

4.2 श्राव्यमानों का प्रयोग

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुर्जों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं के बनाए रखने के लिए मानकीकरण की एक द्विगो की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिए और उन्हें केवल बाण्ड नाम, सूची, संख्या और विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए। बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पों पण्य वस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती-जुलती है और कम से कम उन विशिष्टिकृत के बराबर निष्पादन और गुण उनमें हैं।

4.3 गारण्टी, निष्पादन बांड और शोकी रकमई अमरानि

मागरिक कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारण्टी के लिए कुछ जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक काम जारी रहेगा। यह जमानत या तो बैंक गारंटी द्वारा अथवा निष्पादन बांड द्वारा दी जा सकती है, इसकी धनराशि कार्य की किस्म और परिमाण के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी, लेकिन ठेकेदार में कमी पाए जाने के मामले में ऋणी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। उचित जमानती अवधि को पूरा करने के लिए संविदा के पूर्ण होने

के बाव भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए। गारंटी या अपेक्षित बांड की धनराशि की बोली को दस्तावेजों में निरूपित किया जाता चाहिए।

माल की सप्ताह के लिए संविदाओं में आम तौर पर यह बांछनीय होना कि बैंक गारंटी अथवा बांड की अपेक्षा गारंटी निष्पादन के लिए रोक रखी गई धनराशि के ही कुल भुगतान का प्रतिफल माना जाए। रोक रखी गई धनराशि को कुल भुगतान की दर मानना और इसके अन्तिम भुगतान के लिए शर्तें बोली दस्तावेज में निविष्ट होनी चाहिए। लेकिन, यदि बैंक गारंटी अथवा बांड चुना जाता है तो यह केवल नाम मात्र धनराशि के लिए ही होना चाहिए।

5. चुकाई जाने वाली क्षति

श्रृणी को जब कार्य पूर्ण होने या सुपुर्दगी में देर होने के कारण फालतू खर्च, राजस्व की हानि या अन्य लाभों में नुकसान होता है तो बोली दस्तावेजों में चुकाई जाने वाली क्षति से संबंध प्रावधान शामिल होने चाहिए। ठेकेदार द्वारा संविदा में निविष्ट समय पर अथवा उससे पहले नागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जबकि समय से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य श्रृणी को लाभकारी हो, तो ठेकेदार को बोनस देने की भी व्यवस्था की जाए।

6. बाध्यकारी परिस्थिति

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस संबंध में वाक्यांश होने चाहिए कि संविदा के अन्तर्गत पार्टी द्वारा अपने वायिब्यों को न पूरा करना उस हालत में एक बूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी बूक विवश स्थितियों में (फोर्स मेजोर) के फलस्वरूप हुई है (संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा की जानी है)।

7. झगड़ों का निपटारा

झगड़ों के निपटारे से संबंधित व्यवस्थाएं संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिए। यह बांछनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा बनाए गए "समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमों" पर या अन्य ऐसी व्यवस्थाएं जो भारतीय प्रायातक और विदेशी संभरक दोनों को स्वीकार्य हों, पर आधारित होनी चाहिए।

8. भाषा की व्याख्या

बोली दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिए। यदि बोली दस्तावेजों में अन्य भाषा हस्तमात्र में लायी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि कौन सी भाषा प्रमुख है।

9. बोली बोलना, मूल्यांकन और ठेका देना

9.1. बोलियों के प्रामांजन और बोली प्रस्तुत करने के बीच का समय

बोली तैयार करने के लिए अनुमित समय अधिकार संविदा की महत्वता और पेचीदगी पर निर्भर करेगा। साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 45 दिनों की स्वीकृति दी जानी चाहिए। जहां पर नागरिक निर्माण कार्य अधिक है, वहां पर प्रत्याशित बोलीकारों को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले स्थान पर भली भांति देखभाल करने के लिए आम तौर पर कम से कम 90 दिन दिए जाने चाहिए। किन्तु अनुमित समय प्रत्येक परियोजना से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।

9.2. बोली खोलने की क्रियाविधि

बोलियों की अन्तिम पाबली के लिए और बोली लगाने के लिए तिथि समय और स्थान को बोली प्रामांजन में घोषित किया जाना चाहिए

और सभी बोलियां निर्धारित समय पर खुले आम खोजनी चाहिए। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए। यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दें, गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियों की कुल धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए।

9.3. बोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन

बोली खोलने के पश्चात किसी भी बोली खोलने वाले को उसकी बोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल स्पष्टीकरणों को ही स्वीकार किया जाए जिससे बोली के मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़े, प्रायातक किसी भी बोली खोलने वाले से अपनी बोली के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है, लेकिन बोलीकार या उसकी बोली के सारांश एवं मूल्य परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए।

9.4. गुप्त रखी जाने वाली क्रियाविधि

कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर बोली खोलने के बाद बोली से संबंधित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और निर्णय से संबंधित सिकाफिशों के बारे में भी उस व्यक्ति को जो इन क्रियाविधियों से औपचारिक रूप से संबंधित नहीं है तब तक नहीं बताया जाना चाहिए जब तक कि सफल बोलीकार के लिए संविदा के निर्णय को घोषित नहीं कर दिया जाता है।

9.5. बोलियों की जांच

बोलियों के खोलने के बाद इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि क्या कोई बोलियों के परिकलन में विषय संबंधी गलती तो नहीं लिख दी गई है, क्या बोली दस्तावेज बिल्कुल बोलियों के अनुसार हैं, क्या आवश्यक जमानतों की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत हस्ताक्षरित हैं और क्या बोलियां सामान्यता अन्यथा रूप से सही हैं, यदि बोलियां मूल रूप से विशिष्टीकरण के अनुसार नहीं हैं या उसमें अस्वीकृत शर्तें हैं या अन्यथा रूप से बोली संबंधी दस्तावेजों के अनुसार नहीं हैं तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिए बोलियों के मिलाप के लिए तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिए

9.6. बोलीकार की पूर्ण योग्यताएं

पूर्व योग्यताओं की अनुपस्थिति में प्रायातक को चाहिए कि वह इस बात का सुनिश्चय करे कि उस बोलीकार के पास सम्बद्ध संविदा को प्रभावी रूप से चलाने के लिए क्षमता है और धन है जिसकी बोली का कम से कम मूल्यांकन किया गया है। यदि बोलीकार उन योग्यताओं को पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

9.7. बोलियों का मूल्यांकन और मिलाप

बोलियों का मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार होना चाहिए। गणितीय गलतियों के लिए समंजित बोली की कीमत के अतिरिक्त अन्य बातों जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय, उपकरण की कार्य-कुशलता एवं संगतता या फालतू पुर्जों की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य तरीकों की विश्वसनीयता को विचार में लिया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो वे बातें बोली दस्तावेजों में विशिष्टीकृत मानदण्ड के अनुसार दफ्तर पैसे की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहिए। यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई समंजित कीमत के लिए वृद्धि की धनराशि विचार में नहीं ली जानी चाहिए।

प्रत्येक बोली में मुद्रा अथवा मुद्राएं जिनमें मूल्य प्रांका जाता है बोली स्वीकृत होने पर श्रृणी द्वारा भुगतान किया जाएगा और सभी बोलियों की

गुणता ऋणी द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होनी चाहिए और इसका उल्लेख बोली दस्तावेजों में भी होना चाहिए। मूल्यांकन में उपयोग के लिए विनियम की वर सरकारी स्त्रोत द्वारा प्रकाशित विवरणों पर होनी चाहिए और जब तक निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाए तब तक बोलियों खुलने के दिन उसी प्रकार के भुगतानों पर लागू होंगी चाहिए। ऐसे मामलों में सफल बोलीकार के निर्णय को अधिसूचित करने समय विनिर्माण की दर उपयोग में लाई जानी चाहिए।

9.8 बोलियों को अस्वीकृत करना

बोली दस्तावेजों में सम्बन्धिता यह व्यवस्था की गई है कि ऋणी सभी बोलियों को अस्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन बोलियों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उसी विशिष्टिकरण पर नई बोलियाँ आमंत्रित नहीं की जानी चाहिए। यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहाँ न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जाती है। सभी बोलियों को अस्वीकार करने के लिए तब अधिसूचित्य देने चाहिए जहाँ (क) बोलियों, बोली दस्तावेज के आशय के अनुसार नहीं है या (ख) बहुत कम प्रतियोगिता है। यदि सभी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो ऋणी को चाहिए कि वह उस कारण या उन कारणों की पुनरीक्षा करे जिससे अस्वीकृत मिट्ट की गई है और या तो विशिष्टिकरण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिशोधन पर (या बोलियों के लिए मूल आमंत्रण में मांगी गई पन्थ वस्तुओं की धनराशि पर) या दोनों पर विचार करें। विशेष परिस्थितियों में निधि पर विचार करने के बाद ऋणी संतोषजनक संविदा प्राप्त करने के लिए किसी एक कम से कम बोली देने वाले बोलीकार या दो बोलीकारों के साथ सौदा कर सकता है।

9.9 संविदा का निर्णय

संविदा का निर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निश्चित की गई है और जो क्षमता और वित्तीय साधनों के उचित मानक को पूरा करता है। ऐसे बोलीकार के लिए यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि वह निर्णय को एक शर्त के रूप में विशिष्टिकरण में निर्धारित अन्य वस्तुओं के लिए या अपनी बोली को परिशोधित करने के लिए जिम्मेवारी ले।

अनुबन्ध-3

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र

सं० दि०

सेवा में,

महायन्त्र लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग,
यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली- 110001

विषय :-- येन क्रेडिट सं० (परियोजना सहायता) के अन्तर्गत
जापान से का आयात।

महोदय,

उपर उल्लिखित येन क्रेडिट सं० (परियोजना
सहायता) के अधीन से
जो कि के आयात के संबंध में
..... (बैंक का नाम) जो कि वही होना चाहिए जो नीचे
(क) में सम्बद्ध समुद्रवार संभरक के नाम में साख-पत्र खोलने के लिए

1359 GI/81-2

दिया गया है को प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्न-
लिखित शर्तों प्रस्तुत करते हैं :--

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता
- (ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य, वह तारीख जिस तक वैध है।
- (ग) प्राप्ति के तरीके क्या वह सीधे कर्ष या औपचारिक रूप से अन्तर्गन्तीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।
- (घ) माल का संक्षिप्त विवरण
- (ङ) माल का उद्गम देश
- (च) यदि कोई हो तो पात्र से इन स्त्रोत देशों से आयातित संबद्धकों का प्रतिशत।
- (छ) संविदा का कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (येन में)
- (ज) यदि कोई हो तो भारतीय एजेंट के कमिशन की धनराशि (येन में)
- (झ) वास्तविक जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (येन में) जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है।
- (ञ) समुद्रवार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक
- (ट) समुद्रवार के संभरक का नाम और पता :--
 - (1) राष्ट्रिकता
 - (2) पात्र स्त्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा लिए गए शेषों का प्रतिशत
 - (3) प्रतिनिधि की राष्ट्रिकता और/या संभरक का निवास स्थान
 - (4) उन निवेशकों का प्रतिशत जो मात्र स्त्रोत देशों के राष्ट्रिक हैं।
- (ठ) वे भुगतान शर्तें और संभावित निधि जिनको संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे।
- (ड) सुपुर्वगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि
- (द) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करने समय किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान विधाने द्वारा)
- (ध) पोतबंदान अनुदेश वाहनान्तरण/पार्टशिपमेन्ट की अनुमति की गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए।
- (न) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता
- (थ) क्या उगो लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाएं) कर की गई हैं, और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई है, यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अन्तर्गत ओ०ई० सी० एक० को इसे अधिसूचित किया गया है।

अनुबन्ध - 4

(प्राधिकार-पत्र का प्रपत्र)

संख्या एक
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक ऑफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय:—येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) ऋण करार सं०.....
के अधीन आयात साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करना।

प्रिय सहोदय,

आपके बैंक के साथ 25-3-1980 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्वारा यथा संलग्न व्यौरे के अनुसार सर्वश्री..... के नाम में.....

धन धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साख-पत्र की प्रति आयातक के बैंक, ओ०ई०सी०एफ० भारतीय दूतावास, टोकियो और हमें पृष्ठांकित की जाए।

साख-पत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान आपकी निधि से किया जाएगा। भुगतान के बाद ओ०ई०सी०एफ० को आवश्यक दस्तावेज भेज कर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करना चाहिए।

संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और ओ०ई०सी०एफ० द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि से दोनों के बीच के समय के लिए उपर्युक्त समझौते के अनुसार भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा सीधे ही व्याज दिया जाएगा। बैंकों के अन्य खर्चों जिसमें साख-पत्र खोलने, रख-रखाव करने और साख-पत्रों को जारी रखने के लिए खर्च भी शामिल हैं क्योंकि वे भी परक्राम्य दस्तावेजों के संचालन से संबन्धित हैं और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरकों के बैंकों के खर्चों भी विदेशी संभरक को ही देने पड़ेंगे और इसलिए आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा ओ०ई०सी०एफ० से नहीं किया जा सकता।

यह प्राधिकार पत्र समुद्रपार संभरकों के नाम में साख-पत्र खोलने के लिए है। इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के मद्दे खोले गए धागे के नए साख-पत्र या साख-पत्र में बाद के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जाएगा।

यह प्राधिकार-पत्र..... तक वैध रहेगा।

भवदीय

लेखा अधिकारी

अति निम्नलिखित को प्रेषित:—

1. आयातक.....को उनके पत्र संख्या..... दिनांक..... के संदर्भ में।

2. आयातक के बैंक.....। उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से वस्ता-वेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरक को येन के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपया की गणना सार्वजनिक सूचना संख्या-8 आई०टी०सी० (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना संख्या-184 आई०टी०सी० (पी एन)/68, दिनांक 30-8-68, संख्या-233 आई०टी०सी० (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, संख्या-132 आई०टी०सी० (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, संख्या-74 आई०टी०सी० (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और संख्या-103 आई टी सी (पी एन)/78, दिनांक 12-10-1976 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स एण्ड एक्वायिज 843 मिबिल डिपोजिट/ डिपोजिट्स फार परचेसिज एटसेक्रेट एंड परचेसिज अन्डर क्रेडिट मोन एग्रीमेंट 1979-80 के लिए 5 बिलियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आई टी पी-II फॉर्म दि गवर्नमेंट ऑफ जापान से ऋण" है।

जिन मामलों में मुख्य रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या-132 आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उनके चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रपेण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी:—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
पहली मंजिल, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग,
संवाद मार्ग, नई दिल्ली-110001

जिन मामलों में मुख्य रूप से ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना सं० दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में, जमा किए गए तुल्य रूप का पूरा व्यौरे इस विभाग को भेजना चाहिए।

यदि कोई हो तो, बैंक के खर्चों, व्याज और बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो शाखा के अन्य खर्चों (जिसमें विदेशी संभरकों के बैंकों के खर्चों भी शामिल हैं) प्रमुख लेखाधिकारी विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को समतुल्य रूप भेज करने पर ही तय किए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए इस विभाग द्वारा उचित सलाह बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो भारतीय दूतावास जापान से सम्बद्ध सूचना प्राप्त होने पर ही भेजी जाएगी।

3. निदेशक, ऋण विभाग-2 समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि, टेकबसी म्यूडी बिल्डिंग, 4-1, ओटाडमैयची-1-कॉमे, चियोडा-कू, टोकियो-जापान।

4. भारतीय दूतावास टोकियो।

5. अवर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

अनुबन्ध-5

(प्रो०ई०सी०एफ०एन०सी०-1 प्रपत्र)

अपरिवर्तनीय साख-पत्र

(मान के लिए लागू)

दिनांक

मेवा में,

प्रिय महोदय यह साखपत्र (ऋणी) और
 विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के
 (संभरक का नाम और पता) बीच हुए ऋण करार सं०
 के दिनांक
 के अनुसरण में जारी किया
 गया है।

प्रिय महोदय,

हम सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए बीजक के
 पूरे मूल्य के लिए दर्शनी हुण्डी द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए
 हमने अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं०
 खोल दिया है जो येन (.....
 येन कह सकते हैं) की कुल
 धनराशि से अधिक नहीं है, इसे निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजा
 जाता है।—

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक

कनीन आन बोर्ड, समुद्री पोत लदान बिल जिनमें दिए गए आदेशों
 का पूरा सेट हो बैंक पृष्ठांकित एवं चिह्नित "फ्रेट एवं नोटिफाइ"

अन्य दस्तावेज जिनमें से
 तक लदान का सम्पादन दिया गया हो संविदा संख्या (.....
 यदि कोई हो) के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण प्राणिक पोतलदान स्वीकृत
 है, बाह्यनान्तरण स्वीकृत है।

पोतलदान बिल जो में बाद
 की तिथि का नहीं होना चाहिए। आदेशों को
 19 तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर यह ध्वंजन
 होना चाहिए। "अपरिवर्तनीय साखपत्र सं०
 दिनांक 19 के अन्तर्गत निकलवाया गया
 और आयात सदर्थ संख्या (संख्या) यदि कोई हो, यह क्रेडिट हस्ताक्षरणी
 नहीं है।

हम एतद्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत और इसकी
 शर्तों का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और
 आवेगनी को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए कि क्रेडिट
 "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार डाकुमेंट्स क्रेडिटम (1974 रिवीजन्)
 इंटरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स, पब्लिकेशन सं० 290" के अधीन है।

सौदा करने वाले बैंक के लिए विशेष अनुदेशः—

उपर्युक्त ऋण करार के अन्तर्गत जारी किए गए वचन पत्र की
 व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान
 के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वचन देते हैं कि हम सौदा
 करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हुण्डी की धन-
 राशि को लौटा देंगे।

2. सौदा करने वाले बैंक को यह बताने हुए हम ड्राफ्टस और दस्ता-
 वेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रमाण पत्र अवश्य भेजें कि
 योग्य दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा
 को भेज दिए गए हैं।

3. इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी बैंक के खर्चें आयातक/संभरक के
 लेखों के लिए हैं।

अवधीय

(.....)

वाणिज्यिक बैंक

द्वारा

प्राधिकृत हस्ताक्षर

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साखपत्र सं०
 का एक अभिन्न अंग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि येन
 कुल संविदा मूल्य का
 प्रतिशत है अपेक्षित दस्तावेज लाभकारी विवरण की अन्तिम
 भुगतान तिथि

2. भुगतान वृद्धि

सम्पूर्ण योग की धनराशि येन
 कुल संविदा मूल्य का प्रतिशत
 निम्न प्रकार से भुगतान किया जाता है:—

वेध धनराशि

अन्तिम भुगतान तिथि

येन
 पहली किस्त येन
 दूसरी किस्त येन

अपेक्षित दस्तावेज (ऋणी अथवा उसके समंतीत प्राधिकारी) द्वारा
 जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र
 संलग्न है।

निष्पादन का विवरण

दिनांक
 संदर्भ

सेवा में,

.....

.....

(संभरक का नाम और पता)

संदर्भः—ऋण करार सं० के
 अन्तर्गत परियोजना से संबन्धित
 के नाम में
 येन के लिए द्वारा जारी किए
 गए साखपत्र की सं०
 दिनांक मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रतिनिधि
 (ऋण) एतद्वारा और

(ऋण) एतद्द्वारा श्री
 के बीच समझौता सं
 दिनांक में निहित भुगतान की शर्तों के
 अनुसार समुद्रपार आर्थिक सहायता निधि द्वारा
 की धनराशि (.....) केवल
 प्राप्त करने के लिए एक निष्पादन विवरण जारी करता है।

(.....)
 (ऋणी)

द्वारा
 (प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विशेष अनुदेशः—

वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में वर्णित जाएगा

परिशिष्ट-2

बाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 10

आई टी सी (पी एन)/82, दिनांक 24 फरवरी, 1982 का परिशिष्ट

जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा प्रदान किए गए दूरसंचार परियोजना (4) के लिए येन 9.4 बिलियन के येन क्रेडिट के अधीन माल और सेवाओं के आयात के संबंध में लाइसेंस जर्नल।

खण्ड, 1. सामान्य शर्त

1(1) डाक एवं तार महाविदेशालय की दूर संचार परियोजना की आयात आवश्यकताओं को वित्तपोषण करने के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा प्रदान किया 9.4 बिलियन येन का ऋण विकासशील देशों के लिए खुला है। तदनुसार, इस क्रेडिट के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान और अनुबंध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती है। ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पात्र ज्ञात देश होंगे।

1(2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं सदों और उमी मूल्य के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महाविदेशालय, तकनीकी विकास प्रौद्योगिक माल समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो। इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस (सां) का मूल्य येन 10,500 मिलियन (लागत बीमा भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए।

आयात लाइसेंस का रूप में मूल्य, राजस्व विभाग (सीमा शुल्क) द्वारा अधिमुचित विनियम वर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रवर्तित वर और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं०-78 आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा 2 के अनुसार आयात लाइसेंस में संकेतित वर पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख है कि सीमा शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस (सां) में विनिर्दिष्ट मुद्रा विनियम वर पर लाइसेंस मूल्य के नामे डालेंगे। लाइसेंस पर एक शीर्षक "जापानी येन ऋण सं० आई टी सी-12" होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में "एम/जेसी" कोड होगा। डी०जी०पी० एण्ड टी० को आयात लाइसेंस भेजने समय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र में भी इसे दुहराया जाएगा, जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

1(3) लागत बीमा-भाड़ा के आधार पर केवल डी० जी० पी० एण्ड टी० के नाम में लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

1(4) डी० जी० पी० एण्ड टी० की सुविधा पर निर्भर करने हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस इस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं। लेकिन, कुल मूल्य येन 10,500 मिलियन (लागत बीमा-भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसा कि उपर पैरा (1) में कहा गया है।

1(5) आयात लाइसेंस की वैधता में वृद्धि डी० जी० पी० एण्ड टी० द्वारा आवेदन करने पर 31-12-1985 तक दी जा सकती है। हमने प्राप्ति की वृद्धि यदि कोई हो तो उसके लिए आवेदन आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजा जाना चाहिए।

1(6) क्रेडिट के अधीन विनियमन किए जाने वाले आयात, आयात लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत् स्थापित संलग्न माल और सेवाओं की सूची तक प्रतिबंधित है।

1(7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अधिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अधिकर्ता को भारतीय रूप में किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जाएंगे।

1(8) पक्के अनुदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी संभरकों को जहाज पर्यंत निःशुल्क के आधार पर दिए जाने चाहिए और ये आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीने की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। भाड़ा और बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रूप में भारत में देय होगा। "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन ऋण आदेशों से है जो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ऋण संविदा हों। विदेशी संभरकों के भारतीय अधिकर्ताओं के आदेश या ऐसे भारतीय अधिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं हैं।

1(9) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीने के भीतर वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग डब्ल्यू०ई० अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(8) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सकते इन कारणों का उल्लेख करने हुये लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को स्वयं लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपेक्ष रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय पदाधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों में बैंक गारंटी साख पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र तुल्य रूपया जमा कराने आदि की स्वीकृति सुविधाओं की अनुमति देगे।

1(10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिए। माल के पोतनदान पर अवयव-भरण भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए ठेके में नकद आधार पर अर्थात् पॉल-

मदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी संभरक में भारतीय आयातक को किसी भी किस्म की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए :-

“सात पत्र की प्राप्ति के बाद महीने परन्तु अधिक में अधिक के अन्त तक पूर्ण किया जाना है।”

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निर्दिष्ट करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-12-1985 के बाद की न हो।

खण्ड-2. संभरण ठेके का समाप्ति करते समय ध्यान में रखी जानी वाली विशेष बात

2 (1) ठेके का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य येन से (येन की भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अधिकर्ता का कमीशन यदि या कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए।

भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जब आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2(2) ओ० ई० सी० एफ० येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) के अधीन माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए विस्तृत निवेश अनुबन्ध-2 में दिए गए हैं। साधारणतः माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति औपचारिक खूली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के माध्यम से की जानी चाहिए। लेकिन, यदि माल और सेवाओं के लिए औपचारिक खूली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से भिन्न अधिप्राप्ति क्रियाविधि अपनाने का विचार है जिसका भुगतान ऋण की प्राप्ति में से किया जाएगा तो इसका पूर्व अनुमोदन निधि से प्राप्त किया जाएगा और अधिप्राप्ति क्रियाविधि(यों) अनुमोदन के लिए आवेदन-पत्र विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और कार्गो सहित आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) के माध्यम से निधि को भेजे जाएंगे।

माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए बोलिया आमंत्रित करने से पहले बोलिकाओं के लिए सभी नोटिस, आवेदों, बोली प्रपत्र, प्रस्तावित संविदा, विशिष्टिकरण और ड्राईंग और बोली लगाने से सम्बन्धित अन्य सभी दस्तावेजों की प्रतियां पूर्व अनुमोदन के लिए आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) के माध्यम से निधि को भेजी जाएगी। (ओ० ई० सी० एफ० का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त दस्तावेज/आवेदन) पत्र दो प्रतियों में आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजे जाएंगे।

2(3) विदेशी संभरक का भुगतान, उनके नाम में भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा 1980-81 के लिए ओ० ई० सी० एफ० येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आई० डी० पी०-12 के अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साख्खपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसका व्योम बोधे खण्ड-6 में दिया गया है।

2(4) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संबंध की जानी चाहिए। लेकिन, कुछ विशेष मामलों में, एक से अधिक संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

2 (5) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे या पात्र स्रोत देशों में शामिल किए गए तथा पंजीकृत किए गए पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा शामिल बंध व्यक्ति होंगे।

2 (6) संविदा में घोषणा

प्रत्येक संविदा में संभरक द्वारा पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :-

मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि संभरित किया जाने वाला माल में (पात्र स्रोत देश) उत्पादित है।

मैं, अधोहस्ताक्षरी प्रागे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र स्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित रात्र के अनुसार 30% से कम है :-

आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयात शुल्क
----- × 100

संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य

और

मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा सत्यापित करता हूं कि (पात्र स्रोत देश का नाम)

मैं (कम्पनी का नाम) समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र स्रोत देश के राष्ट्रिकों द्वारा नियमित है।”

2 (7) अपात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयात

जिन वस्तुओं में अपात्र स्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उसका वित्तियन किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार सववार आधार पर आयातित भाग 30% से कम हो :-

आयातित लागत--बीमा भाड़ा मूल्य + आयातक शुल्क
----- × 100

संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य

खण्ड-3. संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली बातें

3(1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए :-

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ० ई० सी० एफ०) के बीच तुर संचार परियोजना (4) के लिए येन क्रेडिट सं० ओ० ई० डी० पी०-12 (परियोजना सहायता) से सम्बन्धित 15 अक्टूबर, 1981 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और वह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा।

(ख) संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ० ई० सी० एफ०) के बीच येन क्रेडिट सं० आई० डी० पी०-12 से सम्बन्धित 15 अक्टूबर, 1981 को हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत बैंक ऑफ इण्डिया टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साख्खपत्र के माध्यम से किए जाएंगे।

(ग) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होंगे जो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओ० ई० सी० एफ० द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हों।

(घ) 2(6) में उल्लिखित प्रपत्र प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में

3(2) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हों तो संभरण संविदा के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को, शामिल माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम से प्रवृत्त कराएगा और पोतलदान कम से कम 6 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास का सूचना देगा जिसमें कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक इच्छुक हों, सूचना की इस अवधि को कम किए जा सकता है। जापानी संभरक का प्रत्येक पोतलदान के पश्चात् आवश्यक ब्यौरे देने हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खण्ड-4. विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ०ई०सी०एफ०) द्वारा ठेके का अनुमोदन

4(1) लाइसेंसधारी को उसके आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर ओ०ई०सी०एफ० टी० और विदेशी संभरकों दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की शर्तें प्रतिपादित की जाने वाली प्रतियां जो विदेशी संभरकों द्वारा लिखित में पृष्ठ आदेश के साथ हो या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां संगत वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियां सहित, जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

4(2) उपर्युक्त क्रियाविधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विषय-वस्तु के लिए अनिवार्य आशोधनों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी।

4(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग 1, दूर संचार परियोजना (3) के लिए येन क्रेडिट में ओ०ई०सी०एफ० टी० (परियोजना सहायता) के अन्तर्गत वित्तदान करने के लिए विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ०ई०सी०एफ०) को संविदा दस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा।

खण्ड-5. विदेशी संभरकों को भुगतान साख्यपत्र क्रियाविधि

5(1) विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ०ई०सी०एफ०) से ठेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग द्वारा ओ०ई०सी०एफ० टी० और सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक को उसकी सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद ओ०ई०सी०एफ० टी० की सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद ओ०ए०ए०ए० टी० कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू०सी०डी० बैंक ब्रिडिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबन्ध-3 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करना चाहिए। ओ०ए०ए०ए० टी० संबंधित विदेशी संभरक के लिए संलग्न प्रपत्र-4 में एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा। जो सम्बद्ध विदेशी संभरक के नाम में (आन्तरिक आयातों के लिए संलग्न अनुबन्ध-5) के रूप में या (सेवाओं के लिए) अनुबन्ध-6 के रूप में अविवर्तनीय साख्यपत्र खोलने के लिए भारतीय बैंक की टोकियो शाखा का भेजा जाता चाहिए। प्राधिकार पत्र की प्रतियां (विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि ओ०ई०सी०एफ०), भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएंगी।

5(2) प्राधिकार पत्र मिलने पर, भारतीय बैंक, टोकियो अनुबन्ध-5 (आन्तरिक आयातों के लिए लागू होता है) या 6 (सेवाओं के लिए लागू होता है) के अनुसार सम्बन्धित विदेशी संभरकों के नाम में अविवर्तनीय साख्यपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ०ई०सी०एफ०) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा।

ओ०ए०ए०ए० टी० से प्राधिकार पत्र के आधार पर साख्यपत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि संविदा संशोधन या अन्यथा के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे सभी प्राधिकार पत्र/साख्यपत्रों के संशोधनों पर स्वतः लागू होगी।

5(3) साल का पोलवतन करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकों के माध्यम से साख्यपत्र में उल्लिखित वस्तावेज भुगतान के लिए बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि वस्तावेज सही पाए गए तो बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो वस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक निधि से प्राप्त करेगा।

5(4) साख्यपत्र को खोलने, रख-रखाव और परिचालन पर किए गए सभी खर्च विदेशी संभरकों के लेख में जाएंगे। अतः भारतीय बैंक, टोकियो संभरक बैंक से सभी खर्च प्राप्त करेगा, वस्तावेजों को सम्भाल के रखने और मोल-तोल करने और अन्य आकस्मिक खर्च भी संभरकों द्वारा किए जाएंगे।

संभरकों को भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा जहाज पर्यन्त निशुल्क साल को सालाना के भुगतान की निधि और ओ०ई०सी०एफ० टी० द्वारा प्रतिपूर्ति की निधि के बीच के समय का व्याज भारतीय बैंक उनके और भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के साथ 25-3-80 को हुए समझौते की शर्तों के अनुसार प्राप्त करेगा और इसकी प्रतिपूर्ति भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा की जाएगी। भारतीय दूतावास, जापान द्वारा व्याज भुगतान पर किया गया खर्च डाक एवं तार विभाग [देखें खण्ड-6(4)] से प्राप्त किया जाएगा।

खण्ड-6. रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व

6(1) भारतीय बैंक, टोकियो सहाय प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट में संकेतित अनुसार ओ०ई०सी०एफ० टी० के प्राधिकृत बैंकर को परन्तम्य जहाजरानी वस्तावेज भेजेगा और बैंकर इसके बदले में यह मुनिश्चय करेगा कि जहाजरानी वस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली में रुपया निक्षेप कर दिया गया है। विदेशी संभरकों को किए गए येन भुगतान के समस्त रुपए सार्वजनिक सूचना सं०-74 आई०टी० सी० (पी० एन०)/74, दिनांक 31-5-1974 में निर्धारित विधि के अनुसार भारत सरकार के लेख में जमा किए जाएंगे। विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समस्त रुपए की गणना करने के लिए आयाती जाने वाली क्षितिम की दर भुगतान की तारीख को लागू क्षितिम की वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं० 109 आई०टी० सी० (पी० एन०)/74, दिनांक 3-8-74 और सं० 8 आई०टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा क्षितिम निवर्तन परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह "के डिपॉजिट्स एंड एडवांज-843 सिविल डिपॉजिट्स—डिपॉजिट्स फार परचजिज एटम्डा एन्ड अन्डर क्रेडिट्स लोन एग्जिस्टेंट" लोन फ्रीम दि गवर्नमेंट ऑफ जापान 9.4 बिलियन येन क्रेडिट सं० आई०टी० सी०-12 फार दूरसंचार परियोजना सं० 4 होना चाहिए।

6(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या सो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी दिल्ली में सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना सं० 184 आई०टी० सी० (पी० एन०)/68, दिनांक 30-8-68, सं० 233 आई०टी० सी० (पी० एन०)/68 दि० 24-10-68, सं० 132 आई०टी० सी० (पी० एन०)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74 आई०टी० सी० (पी० एन०)/74, दिनांक 31-5-74 और सं०-103 आई०टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित तरीके में जमा होना चाहिए।

6(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अनिवार्य धनराशि सेवा खर्च के निमित्त भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए। चालान के विशिष्ट कालों का भरने समय आयातकों/उनके बैंकों को इस बात का मुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 132 आई०टी० सी० (पी० एन०)/71, दिनांक 5-10-71 के पैरा-2 में निर्धारित सूचना चालान के काल में "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण व्योरे" में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित व्योरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए:—

- (क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र संख्या और दिनांक
- (ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं।
- (ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि

उसके पश्चात् सी० ए० ए० एंड ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संशोधन देते हुए और बोजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना खालान रूपों जमा करने का साध्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी० ए० ए० एंड ए० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी :—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक, टोकियो की श्रावणी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतबंदान दस्तावेजों की प्राप्ति 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी० ए० ए० एंड ए० वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

6(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्राप्ति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पंजीकृत करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई को भेजना चाहिए। भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा भारतीय बैंक, टोकियो का व्याज खाते श्राव के सम्बद्ध से बैंक की समतुल्य रूप में किए गए भुगतान की गणना भी उपयुक्त खण्ड-6 की कविका 6(1) में निर्धारित विधि के अनुसार की जाएगी। मुख्य लेखा अधिकारी, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम में जमा किया जाएगा जिसके लिए सी० ए० ए० एंड ए० उचित अनुदेश जारी करने होंगे।

खण्ड-7 विविध व्यवस्थाएं

7(1) आयात लाइसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट

आयातक का पोतबंदान और उसके अग्रोत किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साख पत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू० ए० बैंक विडिंग, संसद मार्ग नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

7(2) संभरकों को विशेष शर्तों के बारे में अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी के आयात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबंधों में संशोधन की प्रवृत्ति करा देना चाहिए जो माल के लाने में संभरक पर प्रभाव डालने हैं।

7 (3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंस और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान में पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुबन्ध-3 में "भुगतान की शर्तें" के अन्तर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से सम्बद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए।

7 (4) भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों में सम्बन्धित या आपाती प्राधिकारियों के साथ घन केडिट समझौते (परियोजना सहायता) सं० आई० डी० पी०-12 के अधीन सभी आभाओं को विदेशी आर्थिक सहयोग विधि, जापान (आई०सी० एफ०) के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए निर्देशों, अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

7 (5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपयुक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

7(6) अनुबन्धों की सूची

1. अनुबन्ध-1	पात्र खोज देशों की सूची
2. अनुबन्ध-2	अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्ग दर्शन
3. अनुबन्ध-3	अधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध
4. अनुबन्ध-4	प्राधिकार पत्र का प्रपत्र
5. अनुबन्ध-5	साख पत्र का प्रपत्र (वास्तविक आयातों के लिए लागू)
6. अनुबन्ध-6	साख पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू)

अनुबन्ध-1

पात्र खोज देशों की सूची

(क) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र

(क-1) ओ० पी० ई० सी० से भिन्न विकासशील देश

1. अफ्रीका उत्तरी सहारा

मिश्र
मोरोको
तुनीशिया

2. अफ्रीका दक्षिणी सहारा

अंगोला
बोत्सवाना
वरण्डी
कैमेरून
केप वर्डी द्वीप समूह
केन्द्रीय अफ्रीका गणतंत्र
चाद
कमोरो द्वीप समूह
कांगो डहिमे का गणतंत्र
भूमध्य गिनी (1)
इथोपिया
नाम्बिया
घाना
गिनी
ग्राइबरी कोस्ट
केनिया
लेसीथे
लाइबीरिया
मालायासी गणतंत्र
मालावी
माली
मारितैनिया मारीशस
मोजाम्बिक
नाइजस
पुर्तगाली गिनी
रियूनियन
रोडे़शिया
रवान्डा
सेन्ट हेलेना और डेप (2)
साओटीम और प्रिन्सीपल
सेनेगल
सिचलीज
सियारा लियोन
सोमालिया
सुडान

स्वा ि लैण्ड
टेरो आफर्स और ह्मास
टोगो
यूगाण्डा
तजानिया संयुक्त गणतंत्र
अपर बोल्डा
जाइरे गणतंत्र
जाम्बिया

3. अमेरिका उत्तरी और केंद्रीय

बहामास
बारबाडोस
बेलीज
बेरमुड
कोस्टारिका
क्यूबा
डोमिनिकन गणतंत्र
एल सल्वेडोर
ग्वाटेमाला
हैती
होण्डुरस
जमैका
मार्टिनिका
मैक्सिको
नीदर लैण्ड एन्टिलीज
निकार गुवा
पनामा
सेन्ट पियरों और मिकलोन
ट्रिनिडाड और टोबागो
वेस्ट इण्डीज (शाखा) एन० प्रार्ह० ई०
(क) सम्बन्धित राज्य (1)
(ख) प्राश्रित (2)

4. दक्षिणी अमेरिका

अर्जेन्टीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलम्बिया
फाल्क लैण्ड द्वीप समूह
फ्रांसीसी गिनी
गुयाना
पाराम्बे
पीरू
सुरिनाम
उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया

बेहरीन
इजराइल
जार्डन
लेबनान
ओमान
मिरिआई अरब गणतंत्र
यूनाइटेड अरब एमीरात (3)
यमन अरब गणतंत्र
यमन जनवादी डी० आर० (4)

- (1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, फर्नेन्डो पो द्वीप सहित
- (2) रिम्नशिप्पित द्वीपों सहित :
असेन्शन, ट्रिस्टन डा डा एक्समिबिल्स, नाइटिंगेल गाफ
- (3) मध्य द्वीप समूह, अरब, बोरेरे क्यूराकाओ, मात्रा, सेन्ट यूस्टा-
मिस सेन्ट मार्टिन (दक्षिणी भाग)

6. दक्षिणी एशिया

अफगानिस्तान
बांग्ला देश
भूटान
यर्मा
भारत
माल द्वीप
नेपाल
पाकिस्तान
श्रीलंका

7. सुदूर पूर्वी (एशिया)

बरुनी
हांगकांग
खमेर गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र
लाओस
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान
थाइलैण्ड
तिमोर
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

8. ओसिनिया

कोक द्वीप समूह
फिजी
गिल्बर्ट और इलास द्वीप
फ्रांसिसी पोलिनेशिया (5)
नीरू
न्यू कलेडोनिया
न्यू हेब्रिडिल हेसिसेम (ब्रा० और फे०)
नियी
पेसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
पापुवा न्यू गिनी
सोमोमन द्वीप समूह (ब्रा०)
टोंगा
वालिस और फुतुना
पश्चिमी ममाओ

9. दक्षिण

साइप्रस
जिब्राल्टर
ग्रीक
माल्टा
स्पेन
सर्बिया
यूगोस्लाविया

- (1) मध्य द्वीप समूह :—पंटिगुबा, डोमिनिका, गेनाडा, सेन्ट किट्स
(सेन्टक्रिस्टोफे) नेविम-एशियुला, सेन्ट लूसिया और सेन्ट
विन्सेंट

- (2) मुख्य द्वीप समूह :—मोन्सेरान, सेमान, तुर्कस और कोईकोस और ब्रिटिश वरजिन द्वीप समूह
- (3) भ्रजमान, दुबई, फुजीहराह, रास अल खेमाह, शारजाह और उम अल कवबेन
- (4) भवन और विभिन्न सुलतनत और भूमिराज सहित ।
- (5) सोसायटी द्वीप समूह (ताहिती सहित) को शामिल करने हुए आस्ट्राल द्वीप समूह टुआमोटु जाम्बीअर ग्रुप और मोकेसस द्वीप समूह ।
- (6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश, कोरोलोन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

(क-2) ओ० पी० ई० सी० के सदस्य या सहयोगी देश

अल्जीरिया
बोलिविया
लिबियान अरब गणतंत्र
रोमान
नाइजीरिया
इक्वेडोर
वेन्जुएला
ईरान
ईराक
कुवैत
कातार
सऊदी अरब
अबुधावी
इण्डोनेशिया

अनुबन्ध-2

ओ० ई० सी० एफ० द्वारा व्यवस्थित परियोजनाओं के अधीन माल और सेवाएं अग्रिमप्रति करने के लिए मुख्य मार्गदर्शन

1. विज्ञापन

प्रोचरारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन सभी निविदाएं बोली प्रामाणित करने के लिए ज्ञानी देश में सामान्य प्रचार के लिए कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञापित होना चाहिए। विज्ञापन के लिए बोली प्रामाणित करने की प्रतियां पात्र स्रोत देशों के स्थानीय प्रतिनिधियों को भी तुरन्त प्रेषित की जानी चाहिए।

2.1 बोली के दस्तावेज और निविदाएं

बोली बाण्ड या बोली की गारंटियां साधारण आवश्यकताएं हैं लेकिन इनको इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उचित बोली-कार हतोत्साह हो जाए। बोली खुलने के पश्चात जैसे ही संभव हो बोली बाण्ड अथवा गारंटियां असफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिए।

2.2 निविदा की शर्तें

निविदा के प्रशासन और उसके अधीन किए गए किन्हीं परिवर्तनों में भी निविदा की शर्तों में आयातक और ठेकेदार या संभरक के अधिकार और दायित्व और यदि आयातक द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त किया है तो उसके अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। निविदा की परम्परागत सामान्य शर्तें, जिनमें से कुछ का उल्लेख इन निदेशन बिन्दुओं में किया गया है के अतिरिक्त परियोजना के स्वल्प और स्थिति के लिए उपर्युक्त विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए।

2.3 निविदाओं की किस्म और आकार

निविदाएं निष्पादित काम के लिए इकाई मूल्य के या आवेदित मर्कों के या एक मुक्त कीमत के या निविदा के विभिन्न भागों के लिए दोनों समन्वय

के आधार पर प्रदान किए जाने वाले माल या सेवाओं के अनुसार की जा सकती है और बोली लगाने वाले दस्तावेजों में चुनी गई निविदा की किस्म की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। वास्तविक मूल्य की प्रतिपूर्ति पर मुख्यतः आधारित निविदाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निधि से स्वीकार्य नहीं हैं। इंजीनियरिंग उपस्कर और निर्माण के लिए उसी पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल निविदाएं (टर्की निविदाएं) यदि ज्ञानी देश के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभ प्रदान करें तो वे स्वीकार्य हैं।

2.4 पात्र संभरक

वे नियतक या संभरक जिनके माल एवं सेवाओं का वित्तदान ज्ञान की रकम में से किया जाना है (जिसे हमके बाद "पात्र संभरक" कहा गया है) पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे:—

- (1) अभिदान किए गए क्षेत्रों का एक बड़ा भाग पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा रखा जाएगा।
- (2) पूर्णकालिक निदेशकों का बहुमत पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों का होगा।
- (3) ऐसे न्यायिक "व्यक्तियों" का पंजीकरण पात्र स्रोत देशों में होगा।

3.1 निविदा की कीमत

(क) निविदा की कीमत जापान येन में दर्शाई जानी चाहिए बशर्ते कि निविदा कीमत का वह भाग जो ठेकेदार ज्ञानी के देश में खर्च करेगा ज्ञानी की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए।

(ख) मुख्य समंजन निविदाएं :—बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि पक्की कीमतों में वृद्धि की आवश्यकता है अथवा बोली की कीमतों में वृद्धि स्वीकार्य है। यदि निविदा के प्रमुख लागत अवयवों अर्थात् श्रम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता है तो निविदा की कीमतों में समंजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

3. कीमतों के समंजन के लिए विशिष्ट सूत्र बोली दस्तावेजों में साफ-साफ परिभाषित होना चाहिए। माल की सप्लाई के लिए निविदाओं में कीमतों के समंजन की उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन सिविल कार्यों के लिए निविदाओं में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को प्रायः शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

एक वर्ष के अन्दर सुपुर्ब किए जाने वाले माल के लिए मुख्य समंजन की व्यवस्था प्रायः नहीं होनी चाहिए। ये मार्ग निर्देशन बिन्दु उन विभिन्न उपायों के परिचय का आभास नहीं कराती हैं जिनके द्वारा निविदा मूल्य समंजित किया जा सके।

(ग) बीमा:—सफल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमे की किस्तों का बोली दस्तावेजों में संक्षेप में वर्णन होना चाहिए।

3.2 दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित निविदा या विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश से समर्थित त्रय आवेदन जो भारतीय प्रायागक द्वारा विदेशी संभरक को दिया गया है, या इनकी फोटो प्रतियां भी फण्ड को स्वीकार्य हैं।

3.3 प्रत्येक निविदा में संभरक की पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :—

"मैं, (हम एतद् द्वारा यह उल्लेख करते हैं कि मेरी (हमारी) कम्पनी पात्र संभरक है क्योंकि क्षेत्रों का -----प्रतिपात (०/०)----- (पात्र स्रोत देश) के राष्ट्रिक है और मेरी (हमारी) कम्पनी ----- (पात्र स्रोत देश) में पंजीकृत कराई गई है।"

4.1 मानवण्ड

यदि उन राष्ट्रीय मानदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए

कि आपान औद्योगिक मानदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड को पूरा करने वाली पण्यपस्तुओं का मानदण्डों की कोटि में बराबर या इससे अधिक मानदण्ड का सुनिश्चित्य करती हैं, उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा।

4.2 बाण्ड नामों का प्रयोग

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुर्जों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए मानकीकरण की एक छिन्नी की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिए और उन्हें केवल बाण्ड नाम, सूची, संख्या और विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए। बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पों वस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिनर्सी-जुलती है और कम से कम उन विशिष्टिकरण के बराबर निष्पादन और गुण उनमें हैं।

4.3 गारंटी, निष्पादन, बांड और रोक रखी गई धनराशि

नागरिक कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारंटी के लिए कुछ जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक काम जारी रहेंगे। यह जमानत या तो बैंक गारंटी द्वारा अथवा निष्पादन बांड द्वारा दी जा सकती है, इसकी धनराशि कार्य की किस्म और परिणाम के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी, लेकिन ठेकेदार में कमी पाए जाने के मामले में ऋणी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

उचित जमानती अवधि को पूरा करने के लिए संविदा के पूर्ण होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए। गारंटी या प्रपेक्षित बांड की धनराशि की बोली को दस्तावेजों में निरूपित किया जाना चाहिए।

माल की सप्पाई के लिए संविदाओं में ग्रामतौर पर यह बांछनीय होगा कि बैंक गारंटी अथवा बांड की प्रपेक्षा गारंटी निष्पादन के लिए रोक रखी गई धनराशि के ही कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए। रोक रखी गई धनराशि को कुल भुगतान की दर मानना और इसके अन्तिम भुगतान के लिए शर्तें बोली दस्तावेज में निरिष्ट होनी चाहिए। लेकिन, यदि बैंक गारंटी अथवा बांड जुना जाता है तो यह केवल नाम मात्र धनराशि के लिए ही होना चाहिए।

5. चुकाई जाने वाली क्षति

ऋणी को जब कार्य पूर्ण होने या सुपुर्दगी में डेर होने के कारण फालतू खर्चों, राजस्व की हानि या अन्य लाभों में नुकसान होता है तो बोली दस्तावेजों में चुकाई जाने वाली क्षति से सम्बन्ध प्राप्तवान शामिल होने चाहिए। ठेकेदार द्वारा संविदा में निरिष्ट समय पर अथवा उससे पहले नागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जब कि समय से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो तो ठेकेदार को बोनस देने की भी व्यवस्था की जाए।

6. बाध्यकारी परिस्थिति

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस संबंध में वाक्यांश होने चाहिए कि संविदा के अंतर्गत पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को न पूरा करना उस हालत में एक बूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी बूक विवश स्थितियों में (फोर्स मेज्योर) के फलस्वरूप हुई है (संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा दी जानी है।)

7. झगड़ों का निपटारा

झगड़ों के निपटारा से सम्बन्धित व्यवस्थाएं संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिए। यह बांछनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय बाणिज्य

मंडल द्वारा बनाए गए "समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमों" पर या अन्य ऐसी व्यवस्थाएं जो भारतीय प्रायातक और विदेशी संभरक दोनों को स्वीकार्य हो, पर आधारित होनी चाहिए।

8. भाषा की व्याख्या

बोली दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिए। यदि बोली दस्तावेजों में अन्य भाषा इस्तेमाल में लायी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि कौन सी भाषा प्रमुख है।

9. बोली खोलना, मूल्यांकन और ठेका देना

9.1 बोलियों के प्रामाण्य और बोली प्रस्तुत करने के बीच का समय

बोली तैयार करने के लिए अनुमति समय अधिकार संविदा की महत्वता और पेचीदगी पर निर्भर करेगा। साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 45 दिनों की स्वीकृति दी जानी चाहिए। जहाँ पर नागरिक निर्माण कार्य अधिक है, वहाँ पर प्रत्याशित बोलीकारों को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले स्थान पर भली-भांति देखभाल करने के लिए ग्राम तौर पर कम से कम 90 दिन दिए जाने चाहिए। किन्तु अनुमित समय प्रत्येक परियोजना से सम्बन्धित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।

9.2 बोली खोलने की क्रियाविधि

बोलियों की अन्तिम पावती के लिए और बोली लगाने के लिए लिखि समय और स्थान को बोली प्रामाण्य में घोषित किया जाना चाहिए और सभी बोलियां निर्धारित समय पर खुले-ग्राम खोलनी चाहिए। इस समय के बाद प्राप्त हुए बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए। यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोलीकार और किसी वैकल्पिक बोलियों की कुल धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए।

9.3 बोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन

बोली खोलने के पश्चात् किसी भी बोली खोलने वाले को उसकी बोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल स्पष्टीकरणों को ही स्वीकार किया जाए जिससे बोली के मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़े, प्रायातक किसी भी बोली खोलने वाले से अपनी बोली के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है, लेकिन बोलीकार या उसकी बोली के सारांश एवं मूल्य परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए।

9.4 गुप्त रखी जाने वाली क्रियाविधि

कानून द्वारा यथा प्रपेक्षित को छोड़कर बोली खोलने के बाद बोली से सम्बन्धित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और निर्णय से सम्बन्धित सिफारिशों के बारे में भी उस व्यक्ति को जो इन क्रियाविधियों से औपचारिक रूप से सम्बन्धित नहीं है तब तक नहीं बताया जाना चाहिए जब तक कि सफल बोलीकार के लिए संविदा के निर्णय को घोषित नहीं कर दिया जाता है।

9.5 बोलियों की जीत

बोलियों के खोलने के बाद इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि क्या कोई बोलियों के परिकलन में विषय संबंधी गलती तो नहीं लिख दी गई है, क्या बोली दस्तावेज बिल्कुल बोलियों के अनुसार हैं, क्या आवश्यक जमानतों की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत हस्ताक्षरित हैं और क्या बोलियां सामान्यता अग्रगण्य रूप से सही हैं, यदि बोलियां मूल रूप से विशिष्टिकरण के अनुसार नहीं हैं या उसमें अस्वीकृत शर्तें हैं या अन्यथा रूप से बोली संबंधी दस्तावेजों के अनुसार नहीं हैं तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिए बोलियों के मिलान के लिए तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिए।

9.6 बोलीकार की पूर्व योग्यताएं

पूर्व योग्यताओं की अनुपस्थिति में आयातक को चाहिए कि वह इस बात का सुनिश्चय करे कि उस बोलीकार के पास सम्बद्ध संविदा को प्रभावी रूप से चलाने के लिए क्षमता है और धन है जिसकी बोली का कम से कम मूल्यांकन किया गया है। यदि बोलीकार उन योग्यताओं को पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

9.7 बोलियों का मूल्यांकन और मिलाप

बोलियों का मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार होना चाहिए। गणितीय गणितियों के लिए संमंजित बोली की कीमत के प्रतिरिक्त अन्य बातों जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय, उपकरण की कार्य कुशलता एवं संगठना या फालतू पुर्जों की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य तरीकों की विश्वसनीयता को विचार में लिया जाना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो वे बातें बोली दस्तावेजों में विशिष्टीकृत मानदण्ड के अनुसार रूपरेखा में की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहिए। यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई समंजित कीमत के लिए वृद्धि की धनराशि विचार में नहीं ली जानी चाहिए।

प्रत्येक बोली में मुद्रा अथवा मुद्राएँ जिनमें मूल्य आका जाता है बोली स्वीकृत होने पर ऋणी द्वारा भुगतान किया जाएगा और सभी बोलियों की तुलना ऋणी द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होनी चाहिए और इसका उल्लेख बोली दस्तावेजों में भी होना चाहिए। मूल्यांकन में उपयोग के लिए विनिमय की दर सरकारी स्रोत द्वारा प्रकाशित विप्रेषण दरों पर होनी चाहिए और जब तक निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाए तब तक बोलियाँ खुलने के दिन उसी प्रकार के भुगतानों पर लागू होनी चाहिए। ऐसे मामलों में सफल बोलीकार के निर्णय को अधिसूचित करने समय विनिमय की दर उपयोग में आई जानी चाहिए।

9.8 बोलियों को अस्वीकृत करना

बोली दस्तावेजों में सामान्यता यह व्यवस्था की गई है कि ऋणी सभी बोलियों को अस्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन बोलियों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उसी विशिष्टीकरण पर नई बोलियाँ आमंत्रित नहीं की जानी चाहिए। यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहाँ न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जाती है। सभी बोलियों को अस्वीकार करने के लिए तब अधीनस्थ देने चाहिए जहाँ (क) बोलियाँ, बोली दस्तावेज के आशय के अनुसार नहीं है या (ख) बहुत कम प्रतियोगिता है। यदि सभी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो ऋणी को चाहिए कि वह उन कारण या उन कारणों की पुनरीक्षा करें जिससे अस्वीकृत सिद्ध की गई है और या तो विशिष्टीकरण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिशोधन पर बोलियों के लिए मूल आमंत्रण में मांगी गई पण्यवस्तुओं की धनराशि पर (या दोनों पर) विचार करें। विशेष परिस्थितियों में निधि पर विचार करने के बावजूद ऋणी संतोषजनक संविदा प्राप्त करने के लिए किसी एक कम से कम बोली देने वाले बोलीकार या दो बोलीकारों के साथ सौदा कर सकता है।

9.9 संविदा का निर्णय

संविदा का निर्णय उसे बोलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निश्चित की गई है और जो क्षमता और वित्तीय साधनों के उचित मानक को पूरा करता है। ऐसे बोलीकार के लिए यह आवश्यक नहीं होता चाहिए कि वह निर्णय को एक शर्त के रूप में विशिष्टीकरण में निर्धारित पण्यवस्तुओं के लिए या अपनी बोली को परिशोधित करने के लिए जिम्मेदारी ले।

अनुबन्ध- 3

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र

मं० दि०

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय :—येन क्रेडिट सं० (परियोजना
सहायता) के अन्तर्गत जापान से का
आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित येन क्रेडिट सं० (परियोजना
सहायता) के अधीन से
जोकि के आयात के संबंध
में (बैंक का नाम) जो कि वही होना
चाहिए जो नीचे (ड) में सम्बद्ध समुद्रपार संभरक के नाम में साख-पत्र
खोलने के लिए दिया गया है, को प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए
हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं :—

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता
- (ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख
जिस तक वैध है।
- (ग) प्राप्ति के तरीके क्या वह सीधे क्रय या औप-
चारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके
मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित
होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय हो तो उपयुक्त न्यूनतम
तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।
- (घ) माल का संक्षिप्त विवरण
- (ङ) माल का उद्गम देश
- (च) यदि कोई हो, तो पाल से इतर जोत देशों से आयातित संघ-
टकों का प्रतिशत।
- (छ) संविदा का कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (येन में)
- (ज) यदि कोई हो, तो भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि
(येन में)
- (झ) वास्तविक जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (येन में) जिसके लिए
प्राधिकार पत्र मांगा गया है।
- (ञ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं
दिनांक
- (ट) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता :—
- (1) राष्ट्रिकता
- (2) पाल ज्ञान देशों के राष्ट्रिकों द्वारा लिए गए श्रेयों का प्रतिशत
- (3) प्रतिनिधि की राष्ट्रिकता और/ या संभरक का निवास स्थान
- (4) उन निदेशकों का प्रतिशत जो पाल ज्ञान देशों के राष्ट्रिक हैं।
- (ठ) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनको संविदा के अन्तर्गत
भुगतान देय होंगे।
- (ड) मुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि
- (ढ) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय किए जाने वाले
दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या उनका निपटान दिखाते हुए)

(ग) पोतलदान अनुदेश बाह्यान्तरण/पार्टशिपमेन्ट की अनुमति दी गई है या नहीं निविष्ट कीजिए ।

(त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता

(थ) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाएं) कर ली गई है और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई है, यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम विमांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अन्तर्गत आई०सी० एफ० को इसे अधिसूचित किया गया है ।

यह प्राधिकार पत्र तक वैध रहेगा ।

अवधीय

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक को उनके पत्र संख्या विमांक के संदर्भ में ।
2. आयातक के बैंक । उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो आंच के वस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को येन के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें । संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपया की गणना सार्वजनिक सूचना सं०-8 आई० टी० सी० (पी०एन०) /76, दि० 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सू० जो समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन को मिश्रित दर पर की जाएगी । यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सीमा शुल्क निकासी के लिए आयातक को सौंपे गए आयात दस्तावेजों के मूल सेट से पहले वे निक्षेप जमा कर दिए गए हैं ।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए । इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं०-184 आई० टी० सी० (पी० एन०) /68, दिनांक 30-8-68, सं०-233 आई० टी० सी० (पी० एन०) /68 दिनांक 24-10-68, संख्या-132 आई० टी० सी० (पी० एन०) /71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई० टी० सी० (पी० एन०) /74, दिनांक, 31-5-74 और संख्या -103 आई० टी० सी० (पी० एन०) /76, दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है । लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स एण्ड एक्वासिज 243 मिलियन डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परचेजिंग एटसेक्टा एवाइ परचेजिंग अन्डर क्रेडिट सोन एग्रीमन्ट 1980-81 के लिए 9.4 बिलियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आई० टी० सी०-12 फेम रि गवर्नमेंट आफ जापान से ऋण है ।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या-132 आई० टी० सी० (पी० एन०) /71, दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकब जमा किया जाता है, उनके बालान की भूख रूप में एक प्रतिनिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण सेते हुए अग्रेशन पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग),
पहली मंजिल, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001.

जिन मामलों में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सं० विमांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दशाना हुण्डा द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए । सभी मामलों में, जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा व्यौरा हम विभाग को भेजना चाहिए ।

यदि कोई हो तो, बैंक के खर्चें, ब्याज और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा के अन्य खर्चें (जिसमें विदेशी संभरकों के बैंकों के खर्चें भी शामिल हैं) प्रमुख लेखा अधिकारी, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को समतुल्य रुपए अदा करने पर हो तय किए जाएंगे । इस प्रयोजन के लिए इस विभाग द्वारा उचित सलाह बैंक आफ इंडिया, टोकियो/भारतीय दूतावास जापान से सम्बन्ध सूचना प्राप्त होने पर ही भेजी जाएगी ।

अनुबन्ध-4

(प्राधिकार पत्र का प्रपत्र)

संख्या एक
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

वियय :—येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) ऋण करार सं० के अधीन आयात साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना ।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 25-3-1980 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्वारा यथा संलग्न स्मूरे के अनुसार सर्वश्री के नाम में येन धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपत्र की प्रति आयातक के बैंक, ओ०ई०सी० एक भारतीय दूतावास, टोकियो और हमें पृष्ठांकित की जाए ।

साखपत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान आप की निधि से किया जाएगा । भुगतान के बाद ओ० ई० सी० एफ० को आवश्यक दस्तावेज भेज कर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करना चाहिए ।

संभरकों को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और ओ० ई०सी०एफ० द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि से दोनों के बीच के समय के लिए उपर्युक्त समझौते के अनुसार भारतीय दूतावास टोकियो द्वारा सीधे ही ब्याज दिया जाएगा । बैंकों के अन्य खर्चें जिसमें साखपत्र खोलने, रख-रखाव करने और साख-पत्रों को जारी रखने के लिए खर्चें भी शामिल हैं क्योंकि वे भी परक्राम्य दस्तावेजों के संचालन से संबंधित हैं और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरकों के बैंकों के खर्चें भी विदेशी संभरकों को ही देने पड़ेंगे और इसलिए आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त किया जा सकता है । इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा ओ०ई०सी०एफ० में नहीं किया जा सकता ।

यह प्राधिकार पत्र समुद्रपार संभरकों के नाम में साख-पत्र खोलने के लिए है । इस मंत्रालय के विभिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के मद्दे खोले गए आगे के नए साख पत्र या साख-पत्रों में दाव के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जाएगा ।

3. निदेशक, ऋण विभाग-2 समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि, टेकनो-म्यूजी बिल्डिंग, 4-1, ओहाट मेची-1 कोसे, विमोडा-नू टोकियो-जोपान ।
4. भारतीय इस्ताबास, टोकियो ।
5. अवर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली ।

लेखा अधिकारी

अनुबन्ध-5

(प्रो० ई० सी० एफ० एल० सी०-1 प्रपत्र)

अपरिवर्तनीय साख-पत्र

(भाल के लिए लागू)

विनांक

सेवा में,

प्रिय महोदय यह साख-पत्र (ऋणी) और विदेशी
..... आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए ऋण
(संभरक का नाम और पता) करार सं०
के विनांक
के अनुसरण में जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए बीजक के पूरे मूल्य के लिए वर्षोनी हुण्डी द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए हमने अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं० खोल दिया है जो येन (..... येन कह सकते हैं) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है, इसे निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजा जाना है :—

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक
क्लीन भाल बोर्ड, समूही पोत लवान बिल जिनमें दिए गए आदेशों का पूरा सेट ही बैंक पृष्ठांकित एवं चिह्नित "फ्रेट" एवं नोटिफाइड

आय्य दस्तावेज जिसमें से तक लवान का सत्यापन दिया गया हो संविदा सं० (यदि कोई हो) के संवर्ध में संक्षिप्त विवरण आर्थिक पोतलवान स्वीकृत है, बाह्यमांतरण स्वीकृत है ।

पोतलवान बिल जो से बाद की तिथि का नहीं होना चाहिए । आदेशिती को 19 तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर यह अंकन होना चाहिए । "अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं० विनांक 19 के अन्तर्गत निकलवाया गया और आयात संवर्ध (संख्याएं) यदि कोई हों" यह क्रेडिट हस्ताक्षरणीय नहीं है ।

हम एतद्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत और इसकी शर्तों का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशिती को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिबत् स्वीकार किए जाएंगे ।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए कि क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार डाकुमेन्ट्स क्रेडिट्स (1974 रिवीजन) इंटरनेशनल चेम्बर ऑफ कामर्स, पब्लिकेशन सं० 290" के अधीन है ।

सौदा करने वाले बैंक के लिए विशेष अनुदेश :

उपर्युक्त ऋण करार के अन्तर्गत जारी किए गए वचन पत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वचन देते हैं कि हम सौदा करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हुण्डी को धनराशि को लौटा देंगे ।

2. सौदा करने वाले बैंक को यह बताते हुए हम ड्राफ्ट और दस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रमाण पत्र अवश्य भेजें कि शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा को भेज दिए गए हैं ।

3. इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी बैंक के खर्चे आयातक/संभरक के लेखे के लिए हैं ।

भवदीय

(.....)
(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा
(आधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान शर्तें :—

यह भुगतान शर्त हमारे साख-पत्र सं० का एक अभिन्न अंग है ।

1. प्रारम्भिक भुगतान
धन राशि येन
कुल संविदा मूल्य का प्रतिशत है
अपेक्षित दस्तावेज :
प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि :
2. मध्यस्त भुगतान (यदि कोई)
धनराशि : येन
कुल संविदा मूल्य का प्रतिशत है
अपेक्षित दस्तावेज :
प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि :
3. पोतलवान दस्तावेजों के मद्दे भुगतान
धनराशि : येन
कुल संविदा मूल्य का प्रतिशत है
टिप्पणी :—पोतलवान दस्तावेजों के मद्दे किए गए पूर्ण भुगतान के मामले में यह संलग्न शीट अपेक्षित नहीं है ।

अनुबन्ध-6

(प्रपत्र प्रो० ई० सी० एफ० एल० सी०-2)

अपरिवर्तनीय साख-पत्र

(सेवाओं के लिए लागू)

विनांक

सेवा में,

..... यह साख-पत्र ऋणी और विदेशी आर्थिक
..... सहयोग निधि के बीच हुए ऋण
..... करार सं०
..... विनांक के
(संभरक का नाम व पता) अनुसरण में जारी किया गया है ।

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए पूर्ण व्योरे मूल्य के लिए लाभकारी ड्राफ्ट एट साइट द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं० (येन पहले) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है।

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (संविदा और परियोजना) से सम्बन्धित वस्तावेजों को नष्टी करना है। सोदा तय करने के लिए ड्राफ्ट से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

सभी ड्राफ्ट और वस्तावेज अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं० दिनांक के अन्तर्गत भुना लिए गए हैं, से विनिर्दिष्ट होने चाहिए।

यह क्रेडिट हस्तांतरणीय नहीं है।

हम एतद्वारा बचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत इसकी शर्तों का अनुपालन करके भुनाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आवेक्षितों की वस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक बताया न जाए, यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार कॉम्मेन्टरी क्रेडिट्स (1974 रिवीजन) इन्टरनेशनल बैंक ऑफ कामर्स, पब्लिकेशन नं० 290" के अधीन है।

सोदा करने वाले बैंक को विशेष अनुवेष्टि :-

इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी और इसके मनोनीत अधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के मूल विवरण को प्राप्ति के पश्चात् इस क्रेडिट के अन्तर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिए। प्रारम्भिक भुगतान के मामले में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बजाए लाभकारी विवरण की आवश्यकता है।

2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए धन बढ़ता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतानों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टों की धनराशि का मोल-मोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रेषित करने का बचन देते हैं।

3. उपर्युक्त मब 1 में यथा उल्लिखित वस्तावेज की एक प्रति और मसौदे में उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे जाएंगे।

4. इस साख के अन्तर्गत बैंक के सभी खर्चें आयातक/संभरक के लेखे के लिए हैं।

भववीय,

(.....)

(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा.....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साखपत्र सं० का एक अभिन्न रंग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि : येन.....

कुल संविदा मूल्य का प्रतिशत है।

अपेक्षित वस्तावेज : लाभकारी विवरण की अन्तिम भुगतान तिथि।

2. भुगतान वृद्धि

सम्पूर्ण योग की धनराशि : येन.....

कुल संविदा मूल्य का प्रतिशत

निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है :-

येन धनराशि अन्तिम भुगतान तिथि

पहली किस्त येन.....

दूसरी किस्त येन.....

अपेक्षित वस्तावेज : (ऋणी अथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी)

द्वारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र संलग्न है।

निष्पादन का विवरण

दिनांक.....

संवर्ध

सेवा में,

.....

.....

(संभरक का नाम और पता)

संवर्ध :- ऋण करार सं० के अन्तर्गत परियोजना से सम्बन्धित के नाम में येन के लिए द्वारा जारी किए गए साख-पत्र की सं० दिनांक मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रतिनिधि (ऋण) एतद्वारा और के बीच समझौता सं० दिनांक में निहित भुगतान की शर्तों के अनुसार समुपहार आर्थिक सहायता निधि द्वारा की धनराशि (..... येन केवल) प्राप्त करने के लिए एक निष्पादन विवरण जारी करता हूं।

(.....)

(ऋणी)

द्वारा.....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विशेष अनुवेष्टि :-

वास्तविक निष्पादन का विवरण संलग्न पत्र में दर्शाया जाएगा।

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 10-ITC (PN)/82

New Delhi, the 24th February, 1982

Import Trade Control

Sub :- Licensing conditions for import of goods and services under the OECF loan agreements No. ID-P. 11 and I.D. P. 12 (Telecommunications Projects Nos. III and IV)

File No. IPC/23/(26)/82.—The terms and conditions governing the issuance of import licence in respect of goods and services under the Yen Credit of 5.0 Billion and Yen 9.4 Billion of the OECF Loan Agreement No. ID-P. 11 and ID-P. 12 for financing the import requirements of the Telecommunications Projects Nos. III and IV of the DGP&T as given in Appendices I & II respectively to this Public Notice are notified for information.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports.

APPENDIX I

LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF IMPORTS
OF GOODS AND SERVICES UNDER THE YEN CREDIT
OF Y 5.0 BILLION FOR TELECOMMUNICATIONS
PROJECT (III), EXTENDED BY THE OVERSEAS
ECONOMIC CO-OPERATION FUND (OECF) OF
JAPAN

Section 1—General Conditions :

1. (i) The Yen Credit of Y 5.0 billion extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Telecommunications Project of the DGP&T is untied in favour of developing countries. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I (ii) Import licence(s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGT/CG Committee. The value of import licence(s) issued under this credit should not exceed Yen 5,600 million, (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78. ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P. 11". The first and second suffix to the licence code will be "S/JC". This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to D.G. P&T, a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (iii) Import licence(s) can be issued only in favour of DGP&T on CIF basis.

I (iv) Depending on the convenience of DGP&T more than one import licence may be issued under this credit, but the total value must not exceed Y 5,600 million (CIF) as specified at (i) above.

I (v) The extension of the validity of the import licence, may on application by DGP&T, be granted upto 31-12-85. Request for further extension, if any, should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I (vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I (viii) Firm order must be placed on FOB basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. Freight and insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I (x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian Importer from the overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

".....Months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of.....".

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-85.

Section-II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II(i) The FOB value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency.

The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II (ii) The broad guidelines for procurement of goods and services under the OECF Yen Credit (Project Aid) are given in Annexure-II. However prior approval of the Fund shall be obtained, if it is proposed to adopt procurement procedures other than Formal Open International Tendering for goods and services to be financed out of the proceeds of the loan, submitting to the Fund an application for approval of procurement method(s) signed by duly authorised person together with its reasoning.

Prior to inviting bids for the procurement of goods and services, the copies of all notices and instructions to bidders, the bid form, the proposed contract, specifications and drawings and all other documents relevant to the bidding shall be submitted to the Fund for its prior approval. The above documents/application may be forwarded, in duplicate, to the DEA (Japan Section) for obtaining approval of OECF.

II(iii) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 11 for 1979-80 the details of which are given in Section VI below.

II (iv) Only one contract should be entered into against the import licence in exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II (v) Eligibility of Supplier

Suppliers shall be nationals of the eligible source countries or juridical persons incorporated and registered in the eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source countries.

II (vi) Declaration in Contract.—The following statements of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I, the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in ——— (eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty percent (30 per cent) in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty} \times 100}{\text{Supplier's FOB Price}}$$

"I, the undersigned, hereby certify that———(Name of company) has been incorporated and registered in——— (name of eligible source country), and is controlled by nationals of the eligible source countries."

II (vii) Permissible imports from non-eligible source countries—Financing of goods which contain materials originating from a non eligible source country or countries may be made provided that the imported portion is less than thirty percent (30 per cent) on an item by item basis in accordance with the following formula:

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}}$$

Section III.—Conditions to be incorporated in the supply contracts.

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts.

(a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 15th Oct, 81 concerning the Yen Credit No. ID-11 (Project Aid) for Telecommunications Project (III) and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.

(b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable Letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo under the Loan Agreement No ID-P, 11 dated 15th Oct., 81; between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

(c) The Overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.

(d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II(vi).

III (ii) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

1359 GI/81—4

Section IV—Contract Approval by OECF

IV (i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contracts duly signed by both DGP&T and overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas suppliers or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

IV (ii) The above procedure will also apply to all contract—amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV (iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen Credit No. ID-P, 11 (Project Aid) for Telecommunication Project (III).

Section V—Payment to the overseas suppliers — Letters of Credit procedur.

V (i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, DGP&T and the CAA&A will be informed of the same. Whereafter the DGP&T should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, (hereinafter referred to as CAA&A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure-III for issue of a letter of authorisation. The CAA&A will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure-IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure-V for physical imports) or Annexure-VI (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V(ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-V (applicable to physical imports) or VI (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA&A would *ipso facto* apply to all such amendments to letter of authorisation/letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V (iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of the goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V. (iv) All charges on account of opening, maintenance, and on the operation of the letter of Credit will be to the account of overseas suppliers. Bank of India Tokyo will therefore recover all these charges from the suppliers Bank, charges for handling and negotiating the documents and other incidentals will also be borne by the suppliers.

For the time lag between the dates of payment of the F.O.B. cost of the material by the B.O.I., Tokyo to the suppliers and the date of reimbursement by the OECF the B.O.I. will charge interest as per the terms and conditions of the Agreement entered into by them with the Government of India (M/o Finance) on 25-3-1980 and get the same reimbursed by the Embassy of India, Tokyo. The expenditure on account of this interest-payment by the Embassy of India in Japan will be recovered from the P&T Department (Vide section VI (iv) infra)

Section VI—Responsibility for rupee deposit

VI (i) The Bank of India, Tokyo will forward the nego-

negotiable shipping documents to the accredited bankers of DGP&T as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the DGP&T make the rupee deposits at RBI, New Delhi or S.B.I. Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. The rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas supplier are to be deposited into Government of India Account in the manner prescribed in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notices No. 109-ITC(PN)/74 dated 3-8-1974 and No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&F or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-843-Civil Deposits—Deposits for purchase etc. abroad—Purchase under credits/Loan Agreements Loans from the Government of Japan—5.0 billion Yen Credit No. ID-11 for Telecommunications Project (III)." The provisions regarding calculation and deposit of interest charges mentioned in the above said Public Notice of 31-5-1974 will, however, not be applicable, as no interest charges are recoverable in respect of imports made by Central Government departments.

VI (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 No. 74-ITC (PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC (PN)/76 dated 12-10-1976.

VI (iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs). While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the Importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury Challans:—

- (a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.
- (b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note : Importers' Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

The rupee equivalents of Yen payments on account of interest charges etc., made by Embassy of India, Tokyo, to BOI, Tokyo will also be calculated in the manner laid down in para VI (i) of Section VI above and deposited in favour of the Principal Accounts Officer, Ministry of External Affairs, New Delhi, for which purpose, CAA&A will be issuing suitable advices.

Section VII—Miscellaneous provisions

VII (i) *Reports on the utilisation of the import licence*
The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made thereagainst and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VII (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VII (iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-III under "Terms of Payment" Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VII (iv) Future Instructions

The license shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P 11 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECP).

VII (v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VII (vi) List of Annexures

- Annexure-I List of eligible source countries
- Annexure-II Main Guidelines for Procurement.
- Annexure-III Request for issue of Letter of Authority.
- Annexure-IV Form of Letter of Authority.
- Annexure-V Form of Letter of Credit (Applicable to Physical Imports).
- Annexure-VI Form of Letter of Credit (Applicable to Services)

ANNEXURE I

List of Eligible Source Countries

A. Developing Countries and Territories

(a) Non-OPEC Developing Countries

I. AFRICA, North of Sahara

Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara

Angola
Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verds Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of
Dahomey

Equatorial Guinea (1)
 Ethiopia
 Gambia
 Ghana
 Guinea
 Ivory Coast
 Kenya
 Lesotho
 Liberia
 Malagasy Republic
 Malawi
 Mali
 Mauritania, Mauritius
 Mozambique
 Niger
 Portuguese Guinea
 Reunion
 Rhodesia
 Rwanda
 St. Helena and dep. (2)
 Sao Tomo and Principe
 Senegal
 Seychelles
 Sierra Leone
 Somalia
 Sudan
 Swaziland
 Terro. Afars and Issas (3)
 Togo
 Uganda
 Un. Rep. of Tanzania
 Upper Volta
 Zaire Republic
 Zambia

III. AMERICA, North and Central

Bahamas
 Barbados
 Belize
 Bermuda
 Costa Rica
 Cuba
 Dominican Republic
 El Salvador
 Guadeloupe
 Guatemala
 Haiti
 Honduras
 Jamaica
 Martinique
 Mexico
 Netherlands Antilles
 Nicaragua
 Panama
 St. Pierre & Miquelon
 Trinidad and Tobago

West Indies (Br.) n.i.e.

- (a) Associated States (4)
 (b) Dependencies (5)

- (1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.
 (2) Including the following islands : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.
 (3) Main islands : Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustacit St. Martin (Southern part).
 (4) Main Islands: Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Christopher), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.
 (5) Main islands: Montserrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.

IV. AMERICA, South

Argentina
 Bolivia
 Brazil
 Chile
 Colombia
 Falkland Islands
 French Guiana
 Guyana
 Paraguay
 Peru
 Surinam
 Uruguay

V. ASIA, Middle East

Bahrain
 Israel
 Jordan
 Lebanon
 Oman
 Syrian Arab Republic
 United Arab Emirates (6)
 Yemen Arab Republic
 Yemen, People's D.R. (7)

VI. ASIA, South

Afghanistan
 Bangladesh
 Bhutan
 Burma
 India
 Maldives
 Nepal
 Pakistan
 Sri Lanka

VII. ASIA, Far East

Brunei
 Hong Kong
 Khmer Republic
 Korea, Republic of
 Laos
 Macao
 Malaysia
 Philippines
 Singapore
 Taiwan
 Thailand
 Timor
 Viet-Nam, Rep. of
 Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. OCEANIA

Cook Islands
 Fiji
 Gilbert & Ellice Is.
 French Polynesia (8)
 Nauru
 New Caledonia
 New Hebrides (Br. and Fr.)
 Niue
 Pacific Islands (US) (9)
 Papua New Guinea
 Solomon Islands (Br.)
 Tonga
 Wallis and Futuna
 Western Samoa

- (6) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.
 (7) Including Aden and various sultanates and emirates.
 (8) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.
 (9) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Island, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam)

IX. Europe

Cyprus
Gibraltar
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

(a2) Member or Association Countries of OPEC

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

ANNEXURE II**Main Guidelines for Procurement of Goods and Services Under the Project Loan as Formulated by O.E.C.F.****I. Advertising**

For all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

II. Bidding Documents and Contracts.**II-1. Bid Bonds or Guarantees.**

Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid bonds or guarantee should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II-2. Conditions of Contract.

The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the importer and contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the importer, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

II-3 Type and Size of Contract.

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items supplied or of a lump sum price, or a combination of both for different portions of the contract, according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable by the Fund except in exceptional circumstances.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts")

are acceptable if they offer technical and economic advantages for the borrower country.

II-4. Eligible suppliers.

Exporters or suppliers whose goods and services are to be financed out of the proceeds of the Loan (hereinafter referred to as "the eligible supplier") shall be nationals of the eligible source countries satisfying the following conditions.

- (1) a majority of subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries,
- (2) a majority of full-time directors shall be nationals of the eligible source countries, and
- (3) such juridical 'persons' shall be registered in the eligible source countries.

III-1. Contract Price.

- (a) The contract price should be stated in Japanese Yen provided, however, that the portion of the contract price which the contractor will spend in the borrower's country should be stated in the borrower's currency.

(b) Price Adjustment Clauses

Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

A provision should be made for adjustment in the contract prices in the event changes occur in the prices of the major cost constituents of the contract, such as labour and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents.

- (c) A ceiling on price adjustment should be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works.

No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.

The Guidelines do not attempt to identify the various methods by which contract prices may be adjusted.

(c) Insurance.

The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successful bidder.

III-2. The contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies are also acceptable to the Fund.

III-3. The following statement of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I (We) hereby state that my (our) company is a eligible supplier, as _____ per cent (_____ per cent) of the shares are held by nationals of _____ (eligible source country), and _____ per cent (_____) of the directors are nationals _____ (eligible source country) and my (our) company has been registered in _____ (eligible source country)".

IV-1. Standards :—If national standard to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

IV-2. Use of Brand Names :—Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

IV-3. Guarantees, Performance Bonds and Retention Money :—Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work, but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. That subject of the guarantee of bond required should be defined with the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance, than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If, however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

V. Liquidated Damage :—Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or less of other benefits to the borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

VI. Force Majeure :—The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the Contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract.)

VII. Settlement of Disputes :—Provision dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the Contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas supplier.

VIII. Language Interpretation :—Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents, English should be added to such documents and it is required to specify which is governing.

IX. Bid Opening, Evaluation and Award of Contract.

IX-1. Time Interval between Invitation and Submission of Bids :—The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

IX-2. Bid Opening Procedures :—The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

IX-3. Clarifications or Alternation of Bids :—No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened, only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The importer may ask any bidder

for a clarification of his bid but should not ask any bidder to change the substance of the price of his bid.

IX-4. Procedures to the confidential :—Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning award should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

IX-5. Examination of Bids :—Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains inadmissible reservations, or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

IX-6. Post-qualification of Bidders :—In the absence of prequalifications, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

IX-7. Evaluation and Comparison of Bids :—Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors, other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of currencies before the award is made. In such cases the exchange rates of the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

IX-8. Rejection of Bids :—Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the costs estimates by a substantial amount. Rejection of all bid may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b), there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revision of the specifications or modification in the project (for amounts of work on items called for in the origin invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

IX-9. Award of Contract :—The Award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities on commodities not stipulated in the specifications or to modify his bid.

ANNEXURE III

REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY

No.

Date :

To

The Controller of Aid Accounts and Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
U.C.O. Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Sub : Import of from Japan under the
Yen Credit No. (Project Aid)

Sir,

In connection with the import of from
under the above mentioned Yen Credit No.
(Project Aid) we furnish the following particulars to enable
you to issue the Letter of Authority to the
(name of the Bank) which should be the same as given in
(n) below for opening a letter of credit in favour of the
overseas supplier concerned.

- (a) Name and Address of the Indian importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.
- (g) Gross FOB value of contract (in Yen).
- (h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any.
- (i) Net FOB value (In Yen) for which the Letter of Authority is required.
- (j) Number and date of the contract with overseas suppliers.
- (k) Name and Address of the overseas supplier :
 - (i) Nationality
 - (ii) Percentage of the shares held by nationals of the eligible source countries.
 - (iii) Nationality of the representative and/or President of the supplier.
 - (iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.
- (l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (m) Expected date of completion of deliveries.
- (n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/part-shipment permitted or not permitted).
- (p) Name and address of the importer's bank in India.
- (q) Whether a contract (s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the O.E.C.F.

ANNEXURE IV

(Letter of Authority Form)

No. F.

Government of India

Ministry of Finance

Department of Economic Affairs

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject : Import under Yen Credit (Project Aid)—Loan
Agreement No. —Issue of Letter of
Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-1980 entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen favouring M/s. as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank; to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

For the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the OECF, you will be paid interests as per terms of the above agreement by the Embassy of India, Tokyo. The other banking charges including those on account of opening maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the overseas suppliers and hence not payable by the importer and may therefore be recovered from the suppliers directly. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto.....

Yours faithfully,

Accounts Officer

Copy forwarded to :—

1. Importer..... with reference to their letter
No. dated.....

2. Importers' Banker They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-68, 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited as 'K-Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad under Purchases under Credit Loan Agreements—Loans from the Government of Japan—5.0 billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. II for 1979-80.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

The banking charges, interest and other charges of the Bank of India, Tokyo Branch (including charges of the overseas suppliers bankers), if any, should be settled by paying their rupee equivalents to the Principal Accounts Officer in the Ministry of External Affairs, New Delhi. For this purpose appropriate advices will be sent by this Department on receipt of relevant information from the Bank of India Tokyo/Embassy of India in Japan.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building, 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

ANNEXURE V
Form OECF-LC I

Irrevocable Letter of Credit
(Applicable for goods)

Date : _____

To _____

(Name and address of
the Supplier)

This letter of Credit has been
issued pursuant to Loan Agreement
No. _____
dated _____

Between (Borrower) and THE
OVERSEAS ECONOMIC COOPERA-
TION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit
No. _____ in your favour for account of _____
for a sum or sums not exceeding any aggregate amount of
Y _____ (Say Yen _____)
available by your drafts at sight for full invoice value
drawn on us, to be accompanied by the following documents :

Signed commercial invoice in _____ Full set
of clean on board ocean bills of lading made out

to order and blank endorsed and marked 'Freight
and "Notify"
Other documents.

Evidencing shipment of (brief description of goods) to be
shipped referring to Contract No. _____ (if any)
from _____ to _____
Partial shipments are _____ permitted.
Transshipment is _____ permitted.
Bills of lading must be dated not later than _____ Draft
must be presented for negotiation not later than _____

All drafts and documents under this credit must be marked
"Drawn under _____ irrevocable credit
No. _____, dated _____ and Import
Reference No. (s), _____ (if any)".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in
compliance with the terms of the credit shall be duly honoured
on due presentation and delivery of documents to the
drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to
"Uniform Customs and Practice for Documentary Credit"
(1974 Revision), International Chamber of Commerce Bro-
chure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After obtaining the reimbursement for our payments from
THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in
accordance with the provisions of the Letter of Commitment
issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement
we undertake to remit the amount of the drafts in accordance
with instructions issued by the negotiating Bank.

2. The negotiating Bank must forward the drafts and one
complete set of documents to us together with the certificate
stating that the remaining documents have been airmailed
direct to _____.

3. All banking charges under this credit are for the account
of the importer/supplier.

Yours faithfully,

(a commercial bank)

By : _____
(Authorised Signature)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our
Letter of Credit No. _____

I. Initial Payment

Amount Y _____
being _____% of the total
contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

II. Intermediate Payment (if any)

Amount : Y _____
being _____% of of the total
contract price.

Required documents:

Latest presentation date :

III. Payment against Shipping Documents

Amount Y _____
being _____% of the total
contract price.

Note : This attached sheet is not required in case of full payment
against shipping documents.

ANNEXURE VI
Form OECF-LC II

Irrevocable Letter of Credit
(Applicable for Services)

Date :

To _____

(Name and address of
the Supplier)

This Letter of Credit has
been issued pursuant to
Loan Agreement No. _____,
dated _____, between
(Borrower) and THE
OVERSEAS ECONOMIC
COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit
No. _____ in your favour for account of for a sum
or sums not exceeding an aggregate amount of Y _____
(Say Yen _____) available by beneficiary's
drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accor-
dance with the Payment Schedule attached hereto,
concerning (Contract No. _____ with regard to _____
Project). Drafts must be presented for negotiation not later
than _____

All drafts and documents must be marked "Drawn under
irrevocable credit No. _____ dated _____"

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in
compliance with the terms of the credit shall be duly
honoured on due presentation and delivery of documents to
the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject
to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
(1974 Revision), International Chamber of Commerce Bro-
chure No. 290."

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After receipt of the original Statement of Performance
issued by (Borrower or its designated authority) in accor-
dance with the form attached hereto, payment(s) under this
credit must be made in accordance with the Payment Schedule
stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial
payments, the beneficiary's Statement is required instead of
the above-mentioned Statement of Performance.

2. After obtaining the reimbursement for our payment from
THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in
accordance with the provisions of the Letter of Commitment
issued thereby under the above mentioned Loan Agreement,
we undertake to remit the amount of the drafts in accordance
with the instructions issued by the negotiating bank.

3. A copy of the document as mentioned in item 1 above
and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt
thereof.

4. All banking charges under this credit are for the account
of the importer/supplier.

Yours faithfully,

(a commercial bank)

By : _____
(Authorized signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our
Letter of Credit No. _____.

I. Initial Payment
Amount Y _____
being _____ % of the total contract price

Required documents : beneficiary's Statement
Latest presentation date :

II. Progress Payment
Aggregate amount Y _____
being _____ % of the total contract
price to be paid as follows :

Amount due	Latest presentation date
------------	-----------------------------

1st Instalment Y _____	_____
------------------------	-------

11nd Instalment Y _____	_____
-------------------------	-------

Required document : a copy of Statement of Performance issued
by (Borrower or its designated authority),
a form of which is attached hereto.

Statement of Performance

Date :
Rf. No.

To _____

(Name and address of the
supplier)

Re: Letter of Credit No. _____, dated _____,
issued by _____
for Y _____ in favour of
_____ concerning _____ Project
under Loan Agreement No. _____

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issue
a Statement of Performance to entitle _____ to receive
the sum of Y _____ (Yen _____ only)
from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND
in accordance with the Payment Terms stipulated in the Con-
tract No. _____, dated _____
between _____ and _____

(Borrower)

By : _____
(Authorised Signature)

Special Instructions:

The details of the actual performance shall be stated in the
sheet attached hereto.

APPENDIX II

**LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF IMPORTS
OF GOODS AND SERVICES UNDER THE YEN CREDIT
OF Y 9.4 BILLION FOR TELECOMMUNICATIONS
PROJECT (IV) EXTENDED BY THE OVERSEAS
ECONOMIC CO-OPERATION FUND (OECF) OF JAPAN**

Section I : General Conditions

1(i) The Yen Credit of 9.4 billion Yen extended by the
Overseas Economic Cooperation fund of Japan (OECF) for
financing the import requirements of the Telecommunication
project of the DGP & T is united in favour of developing
countries. Accordingly the goods and services to be procured

under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I(ii) Import Licence(s) under the Credit can be issued for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD/CG Committee. The value of import licence(s) issued under this credit should not exceed Y 10,500 million, (CIF).

The Rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC (PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI & E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s). This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to DGP&T, a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(iii) Import Licence(s) can be issued only in favour of DGP&T on CIF Basis.

I(iv) Depending on the convenience of DGP&T more than one import licence may be issued under this credit, but the total value must not exceed Y 10,500 million (CIF) as specified at (i) above.

I(v) The extension of the validity of the import licence, may on application by DGP&T, be granted upto 31-12-1985. Request for further extension, if any, should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (vi) Import to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I (vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian Rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I (viii) Firm order must be placed on FOB basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Freight and insurance charges will be payable in Indian rupees. 'Firm orders' means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas supplies and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I (viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee.

Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will be authorised dealers and departmental authorities permit the facility
1359GI/81—5

of letter of authority for the establishment of letter of credit acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I (x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

".....Months after the receipt of letter of credit but to be completed latest by the end of"

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-1985.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract

II(i) The FOB value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's Commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) The board guidelines for procurement of goods and services under the OECF Yen Credit (Project Aid) are given in Annexure-II. Normally the procurement of goods and services should be made through Formal Open International Tendering. However, prior approval of the Fund shall be obtained, if it is proposed to adopt procurement procedures other than Formal Open International Tendering for goods and services to be financed out of the proceeds of the loan, submitting to the Fund on application for approval of procurement method(s) signed by duly authorised person together with its reasoning, through the Department of Economic Affairs (Japan Section).

Prior to inviting bids for the procurement of goods and services the copies of all notices and instructions to bidders, the bid form, the proposed contract, specifications and drawings and all other documents relevant to the bidding shall be submitted to the Fund for its prior approval, through the Department of Economic Affairs (Japan Section).

II (iii) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P12 for 1980-81 the details of which are given in Section VI below.

II (iv) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II (v) Eligibility of Supplier :

Suppliers shall be nationals of the eligible source countries or juridical persons incorporated and registered in the eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source countries.

II (vi) Declaration in Contract :

The following statements of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I, the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in———(eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty per cent (30%) in accordance with the following formula :—

Imported CIF Price + Import Duty × 100"

Supplier's FOB Price

and

"I, the undersigned, hereby certify that———(Name of company) has been incorporated and registered in———

—(name of eligible source country), and is controlled by nationals of the eligible source countries."

II (vii) Permissible imports from non-eligible source countries.

Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty per cent (30%) on an item-by-item basis in accordance with the following formula;

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts

III (i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

- (a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 15th October, 1981 concerning the Yen Credit No. ID-P12 (Project Aid) for Telecommunications Project (IV) and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.
- (b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the Loan Agreement No. ID-P12 dated 15th October, 81 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).
- (c) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.
- (d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II(vi).

III (ii) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by OECF.

IV (i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signed by both DGP&T and Overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the Overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

IV (ii). The above procedure will also apply to all contract—amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV (iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen Credit No. ID-P12 (Project Aid) for Telecommunication Project (IV).

Section V.—Payment to the Overseas Suppliers—Letter of Credit procedure.

V (i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, DGP&T and the CAA&A will be informed of the same. Whereafter the DGP&T should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, (herein-

after referred to as CAA&A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure-III for issue of a letter of authorisation. The CAA&A will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure-IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure-V (for physical imports) or Annexure-VI (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importers Bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V (ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-V (applicable to physical imports) or VI (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's bank in India and the CAA&A.

The above procedure of opening of letter of credit on the basis of the letter of authority from CAA&A would ipso facto apply to all such amendments to letter of authorisation/letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V (iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of the goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V (iv) All charges on account of opening, maintenance and on the operation of the letter of Credit will be to the account of Overseas Suppliers. Bank of India, Tokyo will, therefore, recover all these charges from the Suppliers' Bank, charges for handling and negotiating the documents and other incidentals will also be borne by the suppliers.

For the time lag between the dates of payment of the F.O.B. cost of the material by the B.O.I., Tokyo to the suppliers and the date of reimbursement by the OECF the B.O.I. will charge interest as per the terms and conditions of the Agreement entered into by them with the Government of India (Mio Finance) on 23-3-1980 and get the same reimbursed by the Embassy of India, Tokyo. The expenditure on account of this interest payment by the Embassy of India, in Japan will be recovered from the P&T Department (Vide Section VI(iv) infra).

Section VI—Responsibility for rupee deposit.

VI (i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of DGP&T as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the DGP&T make the rupee deposits at RBI, New Delhi or S.B.I. Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. The rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas supplier are to be deposited into Government of India Account in the manner prescribed in Public Notice No. 74-ITC (PN)/74 dated 31-5-1974. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notices No. 109-ITC(PN)/74 dt. 3-8-1974 and No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. The Head of Account to which the above rupees deposits should be credited is "K-Deposits and Advances—843-Civil Deposits—Deposits for purchase etc. abroad—Purchase under credits/Loan Agreements: Loans from the Government of Japan—9.4 billion Yen Credit No. ID-P12 for Telecommunications Project (IV)" The provisions regarding calculation and deposit for interest charges mentioned in the above said Public Notice of 31-5-1974 will, however, not be applicable, as no interest charges are recoverable in respect of imports made by Central Government departments.

VI(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68, dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68, dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)/71, dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74, dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76, dated 12-10-1976.

VI(iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs). While filing in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury challans :—

- (a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.
- (b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India, should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (DPA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

The rupee equivalents of Yen payments on account of interest charges etc., made by Embassy of India, Tokyo, to the BOI, Tokyo will also be calculated in the manner laid down in para VI(i) of Section VI above and deposited in favour of the Principal Accounts Officer, Ministry of External Affairs, New Delhi, for which purpose, CAA&A will be issuing suitable advices.

Section VII—Miscellaneous provisions.

VII (i) Reports on the utilisation of the import licence

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VII (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VII (iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure III under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VII(iv) Future Instructions

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P.12 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VII (v) Breach of violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VII (vi) List of Annexures

- Annexure I—List of eligible source countries.
- Annexure II—Broad Guidelines for Procurement.
- Annexure III—Request for issue of Letter of Authority.
- Annexure IV—Form of Letter of Authority.
- Annexure V—Form of Letter of Credit (Applicable to Physical Imports.)
- Annexure VI—Form of Letter of Credit (Applicable to Services).

ANNEXURE I

List of Eligible Source Countries

A. Developing Countries and Territories

(a 1) Non-OPEC Developing Countries

I. AFRICA, North of Sahara

Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara

Angola
Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verdes Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of Dahomay
Equatorial Guinea (1)
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania, Mauritius
Mozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda

- (1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

St. Helena and dep. (1)
 Sao Tomo and Principe
 Senegal
 Seychelles
 Sierra Leone
 Somalia
 Sudan
 Swaziland
 Terro. Afars and Issar
 Togo
 Uganda
 Un. Rep. of Tanzania
 Upper Volta
 Zaïre Republic
 Zambia

III. AMERICA, North and Central

Bahamas
 Barbados
 Belize
 Bermuda
 Costa Rica
 Cuba
 Dominican Republic
 El Salvador
 Guadeloupe
 Guatemala
 Haiti
 Honduras
 Jamaica
 Martinique
 Mexico
 Netherlands Antilles
 Nicaragua
 Panama
 St. Pierre & Miquelon
 Trinidad and Tobago

West Indies (Br.) n. i.e.

- (a) Associated States (3)
- (b) Dependencies (4)

IV. AMERICA, South

Argentina
 Bolivia
 Brazil
 Chile
 Colombia
 Falkland Islands
 French Guiana
 Guyana
 Paraguay
 Peru
 Surinam
 Uruguay

- (1) Including the following islands: Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.
- (2) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustacit St. Martin (Southern part).
- (3) Main islands: Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Christopher), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.
- (4) Main islands: Montserrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.

V. ASIA, Middle East

Bahrain
 Israel
 Jordan
 Lebanon
 Oman
 Syrian Arab Republic
 United Arab Emirates (5)
 Yemen Arab Republic
 Yemen, People's D.R. (6)

VI. ASIA, South

Afghanistan
 Bangladesh
 Bhutan
 Burma
 India
 Maldives
 Nepal
 Pakistan
 Sri Lanka

VII. ASIA, Far East

Brunei
 Hong Kong
 Khmer Republic
 Korea, Republic of Laos
 Macao
 Malaysia
 Philippines
 Singapore
 Taiwan
 Thailand
 Timor
 Viet-nam, Rep. of
 Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. OCEANIA

Cook Islands
 Fiji
 Gilbert & Ellice Is.
 French Polynesia (7)
 Nauru
 New Caledonia
 New Hebrides (Br. and Fr.)
 Niue
 Pacific Islands (US) (8)
 Papua New Guinea
 Solomon Islands (Br.)
 Tonga
 Wallis and Futuna
 Western Samoa

XI. Europe

Cyprus
 Gibraltar
 Greece
 Malta
 Spain
 Turkey
 Yugoslavia

- (5) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.
- (6) Including Aden and various sultanates and emirates.
- (7) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.
- (8) Trust Territory of the Pacific Islands: Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

(a2) Members or Association Countries of OPEC

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

ANNEXURE II

Main Guidelines for Procurement of Goods and Services Under The Project Loan as Formulated by Q.E.C.F.

1. Advertising

For all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

II. Bidding Documents and Contracts

II-1. Bid Bonds or Guarantees

Bid bonds or bidding guarantees are as usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II-2. Condition of Contract

The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the importer and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the importer, in the administration of the contract and any Variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are certified to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

II-3 Type and Size of Contract

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items supplied or of a lump sum price, or a combination of both for different portions of the contract, according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable by the Fund except in exceptional circumstances.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantages for the borrower country.

II-4. Eligible suppliers

Exporters or suppliers whose goods and services are to be financed out of the proceeds of the Loan (hereinafter referred to as "the eligible supplier") shall be nationals of the eligible source countries satisfying the following conditions :

- (1) a majority of subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries.
- (2) a majority of full time directors shall be nationals of the eligible source countries and

(3) such juridical 'persons' shall be registered in the eligible source countries.

III-1. Contract Price

(a) The contract price should be stated in Japanese Yen provided, however, that the portion of the contract price which the contractor will spend in the borrower's country should be stated in the borrower's currency.

(b) Price Adjustment Clauses

Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

A provision should be made for adjustment in the contract prices in the event changes occur in the prices of the major cost constituents of the contract, such as labour and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents.

A ceiling on price adjustment should be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works.

No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.

The Guidelines do not attempt to identify the various methods by which contract prices may be adjusted.

(c) Insurance

The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successful bidder.

III-2. The contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies are also acceptable to the Fund.

III-3. The following statement of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I (We) hereby state that my (our) company is an eligible supplier, as _____ per cent (%) of the shares are held by nationals of _____ (eligible source country), and _____ per cent () of the directors are nationals _____ (eligible source country) and my (our) company has been registered in _____ (eligible source country)."

IV-1. Standards

If national standard to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

IV-2. Use of Brand Names

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

IV-3. Guarantees, Performance Bonds and Retention Money

Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of

which will vary with the type and magnitude of the work, but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If, however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

V. Liquidated Damage

Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenue, or loss of other benefits to the borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier-completion would be of benefit to the borrower.

VI. Force Majeure

The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the Contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract.)

VII. Settlement of Disputes

Provision dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the Contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas supplier.

VIII. Language Interpretation

Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents English should be added to such documents and it is required to specify which is governing.

IX. Bid Opening, Evaluation and Award of Contract.

IX-1. Time Interval between Invitation and Submission of Bids.

The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

IX-2. Bid Opening Procedures

The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

IX-3. Clarifications or Alternation of Bids

No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened, only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The importer may ask any bidder for a clarification of his bid but should not ask any bidder to change the substance or the price of his bid.

IX-4. Procedures to be confidential

Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning award should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

IX-5. Examination of Bids

Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains inadmissible reservations, or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsible bid and to enable bids to be compared.

IX-6. Post-qualification of Bidders

In the absence of prequalifications, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

IX-7. Evaluation and Comparison of Bids

Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors, other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of currencies before the award is made. In such cases the exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

IX-8. Rejection of Bids

Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the costs estimated by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b) there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revision of the specifications or modification in the project (or amounts of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

IX-9. Award of Contract

The Award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated

bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities on commodities not stipulated in the specifications or to modify his bid.

ANNEXURE III

Request For Issue of the Letter of Authority

No :

Date :

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
U.C.O. Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Subject.—Import of _____ from Japan under the
Yen Credit No. _____ (Project Aid).

Sir,

In connection with the import of _____ from _____ under the above mentioned Yen Credit No. _____ (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the _____ (name of the Bank) which should be the same as given in (n) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

- (a) Name and Address of the Indian importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.
- (g) Gross FOB value of contract (in Yen).
- (h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any.
- (i) Net FOB value (In Yen) for which the Letter of Authority is required.
- (j) Number and date of the contract with overseas suppliers.
- (k) Name and Address of the overseas supplier :
 - (i) Nationality.
 - (ii) Percentage of the shares held by nationals of the eligible source countries.
 - (iii) Nationality of the representative and/or President of the supplier.
 - (iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.

- (l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (m) Expected date of completion of deliveries.
- (n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/part-shipment permitted or not permitted).
- (p) Name and address of the importer's bank in India.
- (q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the O.E.C.F.

ANNEXURE IV

(Letter of Authority Form)

No. F.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject.—Import under Yen Credit (Project Aid)—Loan Agreement No. _____ Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25th March, 1980 entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen _____ favouring M/s. _____ as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank; to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

For the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the OECF, you will be paid interests as per terms of the above agreement by the Embassy of India, Tokyo. The other banking charges including those on account of opening maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers, if any, are to be borne by the overseas suppliers and hence not payable by the importer and may therefore be recovered from the suppliers directly. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto—.

ANNEXURE V

Yours faithfully,

Accounts Officer

Form OECF-I.C. 1

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for goods)

Copy forwarded to :

Date :

1. Importer— with reference to their letter No. — dated —.

To —

(Name and address of the Supplier)

2. Importer's Banker—. They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76, dated 17th January, 1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No.—, dated —, between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.— in your favour for account of— for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of — (Say Yen—) available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents :

Signed commercial invoice in

Full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight and "Notify

Other documents.

Evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No.— (if any) from— to— Partial shipments are— permitted. Transshipment is— permitted.

Bills of lading must be dated not later than—
Draft must be presented for negotiation not later than—

All drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under— irrevocable credit No.—, dated— and Import Reference No(s).— (if any)."

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.
2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to—.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30th August, 1968, 233-ITC(PN)/68 dated 24th October, 1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5th October, 1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31st May, 1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12th October, 1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits & Advances—843—Civil Deposits—Deposit for purchases etc., abroad under Purchases under Credit/Loan Agreements—Loans from the Government of Japan—94 billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 12 for 1980-81."

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, on the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71, dated 5th October, 1971, should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24th October, 1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

The banking charges, interest and other charges of the Bank of India, Tokyo Branch (including charges of the overseas suppliers bankers), if any, should be settled by paying their rupee equivalents to the Principal Accounts Officer in the Ministry of External Affairs, New Delhi. For this purpose appropriate advices will be sent by this Department on receipt of relevant information from the Bank of India Tokyo/Embassy of India in Japan.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building, 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

3. All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully,

(a commercial bank)

By : _____
(Authorised Signature)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitute an integral par of our Letter of Credit No. _____.

I. Initial Payment

Amount : Y _____
being _____ % of the total
contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

II. Intermediate Payment (if any)

Amount : Y _____
being _____ % of the total
contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

III. Payment against Shipping Documents

Amount : Y _____
being _____ % of the total
contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

Note : This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

ANNEXURE VI

FORM OECF-LC II

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for Services)

To

(Name and address of
the Supplier)

Date :

This Letter of Credit has
been issued pursuant to
Loan Agreement No. _____,
dated _____,
between (Borrower) and THE
OVERSEAS ECONOMIC
COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. _____ in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of _____ (Say Yen _____) available by beneficiary's drafts at sight for full statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, _____ concerning (Contract No. _____ with regard to _____ Project). Drafts must be presented for negotiation not later than _____.

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No. _____ dated _____".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290."

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto payment(s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's Statement is required instead of the above-mentioned Statement of Performance.
2. After obtaining the reimbursement for our payment from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.
3. A copy of the document as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.
4. All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully,

(a commercial bank)

By : _____
(Authorised Signature)

Payment Schedule

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No. _____.

I. Initial Payment

Amount : Y _____
being _____% of the total contract price

Required documents : beneficiary's Statement

Latest presentation date :

II. Progress Payment

Aggregate amount : Y _____
being _____% of the total contract price
to be paid as follows :

Amount due	Latest presentation date
_____	_____

Ist Instalment : Y _____

IInd Instalment Y _____

Required document : a copy of Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto.

Statement of Performance

Date :

Ref. No.

To _____

(Name and address of the supplier)

Re : Letter of Credit No. _____, dated _____, issued by _____ for Y _____ in favour of _____ concerning _____ Project under Loan Agreement No. _____

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issue a Statement of Performance to entitle _____ to receive the sum of Y _____ (Yen only) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No. _____, dated _____ between _____ and _____

(Borrower)

By : _____
(Authorised Signature)

Special Instructions :

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.